CNEWS सिटी चीफ

सिटी चीफ

वर्ष-15, अंक-96
पृष्ठ-8 मूल्य 2 रूपया

सम्पूर्ण भारत मे चर्चित हिन्दी अखबार

CITYCHIEFSENDMENEWS@GMAIL.COM

इंदौर , गुरुवार, 11 जुलाई 2024

आज का विचार

कांच के टुकड़े बनकर रहोगे तो कोई तुम्हें छुऐगा भी नहीं..

जिस दिन दर्पण बन जाओगे तो बिना देखे कोई रहेगा नहीं..

सिंगल कॉलम

पाकिस्तान में नहीं खेलेगी टीम इंडिया, चैंपियंस ट्रॉफी के मैच इन देशों में कराने की मांग

नई दिल्ली। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में होना है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस बार काफी उम्मीदें लेकर चल रहा था कि पूरी ट्रॉफी पाकिस्तान में ही खेली जाएगी। भारतीय टीम अपने सभी मैच लाहौर में खेलेगी, लेकिन अब बड़ी खबर न्यूज एजेंसी एएनआई की तरफ से आई है। जिसके मुताबिक, भारतीय टीम, चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं जाएगी। चैंपियंस ट्रॉफी हायब्रिड मॉडल पर खेली जाएगी। भारत के मैच दुबई या श्रीलंका में खेले जा सकते हैं। भारतीय खिलाड़ी भी पाकिस्तान जाने के पक्ष में नहीं! मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, टीम इंडिया के कुछ खिलाड़ी भी पाकिस्तान जाने के पक्ष में नहीं हैं। वह चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं जाना चाहते हैं। लिहाजा, बीसीसीआई ने भी कदम पीछे खीच लिया है। रिश्ते सुधारना पाकिस्तान की भी जिम्मेदारी भारतीय टीम के पाकिस्तान नहीं जाने को लेकर जम्मू कश्मीर और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुला ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि यह फैसला बीसीसीआई को करना है, लेकिन दोनों देशों की बीच रिश्ते सुधारना सिर्फ भारत का काम नहीं है। यह पाकिस्तान की भी जिम्मेदारी है।

अमरवाड़ा में 78.7 प्रतिशत मतदान, पिछली बार से लगभग 10 प्रतिशत कम

अमरवाड़ा। अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव के लिए बुधवार को मतदान संपन्न हो गया। एक दो घटनाओं को छोड़कर शांतिपूर्ण मतदान हुआ। शाम 7:00 बजे तक मतदान प्रतिशत 78.7 तक पहुंच चुका था। हालांकि ये पिछली बार से लगभग 10 प्रतिशत कम है। 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में अमरवाड़ा सीट पर 88.63 मतदान हुआ था। यहां भाजपा, कांग्रेस और गोंडवाना में मुकाबला देखा जा रहा है। भाजपा से पूर्व विधायक राजा कमलेश शाह चुनावी मैदान में हैं तो वहीं कांग्रेस से धीरेन शाह अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं गोंडवाना से देवरावेन चुनाव लड़ रहे हैं। तीनों के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। बता दें कि सुबह 7.00 से 10.00 तक मतदान की गति काफी धीमी रही। दोपहर के बाद मतदान प्रतिशत 50 पार हो गया था। वहीं शाम होते-होते मतदान प्रतिशत 78 तक पहुंच गया। अच्छे मतदान प्रतिशत के बाद प्रशासन ने राहत की सांस ली है। विधानसभा उपचुनाव के बीच मानेगांव पंचायत के नांदिया में मूलभूत सुविधाओं को लेकर चुनाव बहिष्कार कर दिया था, जिसके बाद जनपद पंचायत सीईओ और भाजपा नेताओं की समझाइश और सांसद से बातचीत के बाद मामला शांत हो पाया, हालांकि कुछ लोगों ने इसके बाद भी मतदान नहीं किया।

पूर्वी लद्दाख में तस्करी कर लाया गया 108 किलो सोना जब्त, दो गिरफ्तार

नई दिल्ली। भारत-तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी ने पूर्वी लद्दाख के सिरिगापल के पास 108 किलोग्राम वजन के 108 सोने के बिस्कुट जब्त किए हैं। आईटीबीपी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, 21वीं बटालियन के डिप्टी कमांडेंट दीपक भट्ट के नेतृत्व में एक टीम ने लंबी दूरी की गश्त करते हुए इसे जब्त कर लिया। आईटीबीपी ने कहा, दो संदिग्धों को पकड़ लिया गया है और अन्य एजेंसियों के साथ जांच जारी है। 21 बटालियन आईटीबीपी के जवानों ने घोड़ों के साथ दो तस्करों से 108 किलोग्राम सोने की खेप पकड़ी। दोनों आरोपियों की पहचान त्सेरिंग चिनबा और स्टैनजिन दोरग्याल निवासी कोयुल, न्योमा के रूप में हुई है। अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) के पास कोयुल गांव में एक व्यक्ति के घर में कई करोड़ रुपए का सोना रखा हुआ था। इसकी खुफिया जानकारी मिल रही थी। इन सूचनाओं पर कार्रवाई करते हुए आईटीबीपी और स्थानीय पुलिस ने सोने की जब्ती की है। दोनों ने कथित तौर पर सोने की तस्करी की और इसे गांव में अपने घर पर रखा। मामले में लद्दाख पुलिस की जांच चल रही है।

मोहन सरकार खरीदेगी कनाडा का बॉम्बार्डियर चैलेंजर 3500 विमान

भोपाल। मध्यप्रदेश की डॉ. मोहन यादव सरकार ने कनाडा की कंपनी बॉम्बार्डियर के चैलेंजर 3500 विमान को खरीदने का फैसला किया है। मध्य प्रदेश सरकार के पास 2021 से कोई विमान नहीं था। तब से ही नया विमान खरीदने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, जो अब पूरी हो चुकी है। दो कंपनियों ने अपने प्रस्ताव दिए थे। इसमें से चैलेंजर 3500 का प्रस्ताव एल-1 कैटेगरी में चुना गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। मध्यप्रदेश सरकार ने कनाडा की कंपनी बॉम्बार्डियर इंक के चैलेंजर 3500 मॉडल को 233 करोड़ रुपये में खरीदने का फैसला किया है। दरअसल, छह मई 2021 को ग्वालियर में लैंडिंग के दौरान विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। कंपनी ने उस विमान को बियॉन्ड रिपेयर करार दिया। यानी उसकी मरम्मत नहीं हो सकती थी। उसके बाद से राज्य सरकार के पास कोई विमान नहीं था और नया विमान खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। इस दौरान कनाडा की कंपनी की बोली सबसे कम रही। साथ ही निविदा शर्तों में जो आवश्यकताएं बताई गई हैं, उसे चैलेंजर 3500 पूरी करता है।

20 माह में आएगा नया विमान

नया चैलेंजर 3500 विमान 20 माह में मिलेगा। सरकार की आवश्यकता के अनुसार कंपनी इस विमान को आठ सीटर बना रही है। इसकी कीमत 233 करोड़ रुपये बताई जा रही है। इसका मतलब यह है कि डॉ. मोहन यादव को अगले 20 माह किराये के विमान में ही उड़ान भरनी होगी। चैलेंजर 3500 अपनी श्रेणी में सबसे अधिक एडवांस तकनीक से बना है। इसमें इंडस्ट्री का पहला वॉयस-कंट्रोल्ड केबिन और नए जमाने की सीटें लगी हैं। चैलेंजर 3500 विमान स्थिरता, प्रदर्शन और विश्वसनीयता का बेहतरीन मिश्रण प्रदान करता है, जिसके सहारे आप किसी भी मौसम में लंबी उड़ान भर सकते हैं।

बेहतरीन केबिन अनुभव

चैलेंजर 3500 बेहतरीन केबिन अनुभव प्रदान करता है। इसे 2022 रेड डॉट के बेस्ट ऑफ बेस्ट प्रोडक्ट डिजाइन से भी पुरस्कृत किया जा चुका है। यह विमान के इंटरनेशनल लेवल पर बेहतरीन होने की पुष्टि करता है। इस विमान की खासियत यह है कि 4,850 की कम से कम ऊंचाई और 41 हजार फीट की अधिकतम ऊंचाई पर भी यह जमीन पर होने का अहसास देता है। एयर सर्कुलेशन की तकनीक ऐसी है कि सिर्फ दो मिनट में यह ताजा हवा से केबिन को भर देता है। इससे यात्रियों के लिए ताजगी भरा अहसास बना रहता है।

सेकुलर कानून ही चलेगा: सीआरपीसी की धारा 125 सभी महिलाओं पर लागू होगी, चाहे उनका धर्म कोई भी हो

मुस्लिम महिलाएं भी गुजारा भत्ते की हकदार

पति-पत्नी मिलकर खुलवाएं ज्वाइंट अकाउंट, जरूरत होने पर पत्नी निकाल सके एटीएम से पैसे

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के पक्ष में एक बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि ऐसी महिलाएं सीआरपीसी की धारा 125 के तहत अपने पति से भरण-पोषण की मांग कर सकती है। वे गुजारा भत्ते की हकदार हैं। देश की सर्वोच्च अदालत ने साफ-साफ शब्दों में कहा कि देश में सेकुलर कानून ही चलेगा। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टिन गॉर्ज मसीह की पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि मुस्लिम महिलाएं गुजारा भत्ता के लिए कानूनी अधिकार का इस्तेमाल कर सकती हैं। वे सीआरपीसी की धारा 125 के तहत याचिका दायर कर सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि यह धारा सभी विवाहित महिलाओं पर लागू होती है, चाहे उनका धर्म कोई भी हो।

आपको बता दें कि अब्दुल समद नाम के एक मुस्लिम शख्स ने पत्नी को गुजारा भत्ता देने के तेलंगाना हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। उसने दलील दी थी कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला सीआरपीसी की धारा 125 के तहत याचिका दायर करने की हकदार नहीं है। महिला को मुस्लिम महिला अधिनियम, 1986 अधिनियम के प्रावधानों के तहत ही चलना होगा। लेकिन कोर्ट ने ऐसे मामलों में सीआरपीसी की धारा 125 को प्राथमिकता दी।पीठ ने याचिका को खारिज करते हुए यह स्पष्ट किया कि यदि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत याचिका लंबित रहने के दौरान कोई मुस्लिम महिला तलाकशुदा हो जाती है तो वह मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम 2019 का सहारा ले सकती है। पीठ ने कहा कि इस अधिनियम के तहत किए गए उपाय सीआरपीसी की धारा 125 के तहत उपाय के अतिरिक्त है।

गुजारा भत्ता देना दान नहीं...

अपने फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुजारा भत्ता देना दान नहीं बल्कि शादीशुदा महिलाओं का मूलभूत अधिकार है। अदालत ने कहा कि ये अधिकार धर्म की सीमाओं से परे है और सभी विवाहित महिलाओं के लिए लैंगिक समानता और आर्थिक सुरक्षा के सिद्धांत को मजबूत करता है। जज नागरत्ना ने फैसला सुनाते हुए कहा कि हम इस अपील को खारिज करते हैं, हमारा मुख्य निष्कर्ष ये है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 सभी महिलाओं पर लागू होगी, सिर्फ शादीशुदा महिलाओं पर ही नहीं।

पुरुषों को सुप्रीम कोर्ट की नसीहत

सुप्रीम कोर्ट ने इस अहम फैसले में यह भी कहा कि अब भारतीय पुरुषों को यह समझने का वक्त आ गया है कि घर चलाने में गृहिणियों की भूमिका और उनके त्याग कितने अहम होते हैं। कोर्ट की पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि पति को अपनी पत्नी को आर्थिक मदद देनी चाहिए। साथ ही ये भी सुझाया कि पति-पत्नी मिलकर बैंक खाता खोलें और एटीएम का कार्ड भी दोनों के पास रहे। इससे घर में महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। कोर्ट ने कहा कि पतियों को गृहणियों के लिए ज्वाइंट अकाउंट खोलने और एटीएम तक की पहुंच आसान बनाने की जरूरत है। पीठ ने कहा, पतियों द्वारा अपनी पत्नियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की आवश्यकताओं पर खास ध्यान देना चाहिए। ज्वाइंट बैंक अकाउंट रखने और एटीएम तक पहुंच साझा करने जैसे व्यावहारिक उपाय घर में महिलाओं के लिए सुलभ होने चाहिए।

शाहबानो मामले में भी था यह फैसला

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा था कि सीआरपीसी की धारा 125 एक धर्मनिरपेक्ष प्रावधान है जो मुस्लिम महिलाओं पर भी लागू होता है। हालांकि मुस्लिम महिला अधिनियम, 1986 द्वारा इसे निरस्त कर दिया गया और 2001 में कानून की वैधता को बरकरार रखा गया। दरअसल सीआरपीसी की धारा 125 में पत्नी, संतान और माता-पिता के भरण-पोषण को लेकर विस्तार से जानकारी दी गई है। इस धारा के अनुसार पति, पिता या बच्चों पर आश्रित पत्नी, मां-बाप या बच्चे गुजारे-भत्ते का दावा केवल तभी कर सकते हैं, जब उनके पास आजीविका का कोई और साधन उपलब्ध नहीं हो।

तबादला नीति का प्रारूप तैयार

मप्र में तबादलों पर से जल्द हटेगा बैन, 15 दिन का मिलेगा समय

भोपाल। मध्यप्रदेश में करीब एक साल से भी ज्यादा समय से तबादले का इंतजार कर रहे हजारों सरकारी कर्मचारियों को जल्दी ही अच्छी खबर मिलने जा रही है। सरकारी अधिकारियों-कर्मचारियों के तबादले पर प्रतिबंध अब जल्द हटने वाले हैं। सरकार 15 दिन के लिए सभी विभागों को प्रशासनिक और स्वैच्छिक आधार पर तबादले करने की अनुमति देगी। सरकार ने तबादला नीति का प्रारूप भी तैयार कर लिया है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव मंत्रियों से विचार-विमर्श करने के बाद नीति को अंतिम रूप देंगे। बता दें कि 1 जुलाई से ही कर्मचारियों की ट्रांसफर की हलचल शुरू हो जाती है। अब इसके लिए नीति बनना भी शुरू हो चुकी है। इस ट्रांसफर नीति के तहत किसी भी संवर्ग में 20 प्रतिशत से अधिक तबादले नहीं किए जा सकेंगे। आपको बता दें कि प्रदेश में 2021 में तबादला नीति घोषित की गई थी। उस समय जुलाई में एक माह के लिए तबादले से प्रतिबंध हटाया गया था। इसके बाद नीति घोषित नहीं की गई, लेकिन मुख्यमंत्री समन्वय के माध्यम से तबादले होते रहे। वहीं, वर्ष 2023 में विधानसभा चुनाव की मतदाता सूची की तैयारी के चलते निर्वाचन कार्य से सीधे जुड़े कलेक्टर, अपर कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, शिक्षक और पटवारियों के स्थानांतरण पर प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन अब तबादले होना शुरू हो जाएंगे। इस दौरान जिले से जिले के अंदर तबादले के अधिकारी प्रभारी मंत्रियों को दिये जाएंगे। प्रथम श्रेणी के सभी अधिकारियों के तबादले मुख्यमंत्री के अनुमोदन से होंगे। द्वितीय और तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के विभागीय मंत्री और जिले के भीतर कर्मचारियों के तबादले कलेक्टर के माध्यम से होंगे। हालांकि इसके लिए प्रभारी मंत्री की परमिशन लेना अनिवार्य होगा। उनकी परमिशन के बाद ट्रांसफर होंगे। तबादला नीति का पालन सुनिश्चित करने का दायित्व विभागीय अधिकारियों को दिया गया है।

अगले पांच साल के रोड मैप पर काम शुरू

बिना बैग स्कूल जाएंगे बच्चे! शिक्षा मंत्रालय ने शुरू की तैयारी

नई दिल्ली। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत तय किए लक्ष्यों को हासिल करने के लिए अगले पांच वर्षों के रोड मैप पर मंथन शुरू किया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने समीक्षा बैठक में कहा कि राज्यों और केंद्र दोनों को ही शिक्षा इकोसिस्टम को मजबूत बनाने और एक-दूसरे राज्यों में बेस्ट प्रैक्टिस को आगे बढ़ाने के लिए एक टीम के रूप में काम करना चाहिए। उन्होंने पूरे देश में स्कूली शिक्षा के समग्र विकास के लिए अगले पांच वर्षों के रोडमैप के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि शिक्षा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन का एक प्रमुख स्तंभ है और राज्यों को इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के करीब चार वर्षों में देश में शिक्षा इकोसिस?टम ने तेजी से प्रगति की है। इस मौके पर केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी भी मौजूद रहे।

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने स्कूलों में 'बैगलेस डेज' को लेकर तैयार की गई गाइडलाइंस की समीक्षा की। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव संजय कुमार ने एनसीईआरटी की यूनिट की ओर से तैयार गाइडलाइंस पर सीबीएसई, एनसीईआरटी, केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय संगठन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। यह तय किया गया है कि समीक्षा के बाद अब जल्द ही इन दिशा- निर्देशों को अंतिम रूप दिया जाएगा। स्कूलों के वार्षिक कैलेंडर में 10 बैगलेस डे होंगे। यानी इन दस दिन छात्र बिना बैग और किताबों के स्कूल जाएंगे। इन दिनों में छात्रों को फील्ड विजिट करवाई जाएगी। यह सिफारिश की गई है कि इन दस दिनों में छात्रों को स्थानीय पारिस्थितिकी के बारे में जागरूक करने, उन्हें पानी की शुद्धता की जांच करना सिखाने, स्थानीय वनस्पतियों और जीवों को पहचानने और स्थानीय स्मारकों का दौरा करवाया जाए। शिक्षा मंत्री ने कहा कि भारत एक युवा देश है। हमारी चुनौती 21वीं सदी की दुनिया के लिए वैश्विक नागरिक तैयार करना है, जो तेजी से बदल रही हैं क?योंकि यह सदी प्रौद्योगिकी की ओर से संचालित हो रही है।

सिविल सेवा के इतिहास में पहली बार जेंडर चेंज पर नाम बदलने की इजाजत

नई दिल्ली। हैदराबाद में तैनात एक महिला अधिकारी लिंग परिवर्तन कराकर युवक बन गई हैं। इस अधिकारी ने अपना नाम भी बदल लिया है। अब इस अधिकारी का नाम एम अनुसूया से अनुकाथिर सूर्या हो गया है। इस फैसले की मंजूरी वित्त मंत्रालय की ओर से भी मिल गई है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) अधिकारी को नाम और लिंग बदलने की अपील को मंजूरी दे दी। यह भारतीय सिविल सेवा के इतिहास में पहली बार हुआ है। आदेश के अनुसार सुश्री एम अनुसूया,आईआरएस ने मंत्रालय से उनके नाम को अनुकाथिर सूर्या और लिंग को महिला से पुरुष में बदलने की स्वीकृति मांगी थी जिसे मंजूरी मिल गई है।

यह कहा गया मंत्रालय के आदेश में

मंत्रालय के आदेश में कहा गया है कि अधिकारी के अनुरोध पर विचार किया गया और उसे मंजूरी दे दी गई है। आदेश में लिखा है, सुश्री एम अनुसूया के अनुरोध पर विचार किया गया। इसलिए अब से इस अधिकारी को सभी आधिकारिक दस्तावेजों में श्री एम अनुकाथिर सूर्या के रूप में मान्यता दी जाएगी।

कई वरिष्ठ अधिकारियों ने की प्रशंसा

इस फैसले की कई वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रशंसा भी की है। अधिकारियों का कहना है कि यह यह एक अभूतपूर्व आदेश है। हमें अधिकारी और हमारे मंत्रालय पर भी गर्व है। यह आदेश मुख्य आयुक्त, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, सेवा कर अपीलीय ट्रिब्यूनल और सीबीआईसी के अंतर्गत सभी प्रमुख मुख्य आयुक्तों/प्रधान महानिदेशकों को भेजा गया है।

पूरी करनी होती हैं कई औपचारिकताएं

जेंडर चेंज कराने से पहले कई मंजूरी भी हासिल करनी होती है। एक बार कोई लिंग परिवर्तन का फैसला करता है तो उसे इसका हलफनामा तैयार करना पड़ता है। इस हलफनामे के जरिये लिंग परिवर्तन की जानकारी देनी होती है। नोटरी वाले इस हलफनामे में नाम, पिता का नाम, आयु और लिंग संबंधी जानकारी देनी होती है। यदि कोई सरकारी विभाग में कार्यरत है तो उसे अपने संबंधित अधिकारी और विभाग को भी इस बारे में जानकारी देनी होती है।

सिंगल कॉलम

सफाई में लापरवाही पर दो सहायक दरोगा का पांच-पांच दिन का कटेगा वेतन

इंदौर। नगर निगम कमिश्नर ने निरीक्षण के दौरान सफाई व्यवस्था ठीक नहीं मिलने पर दो सहायक दरोगा के 5-5 दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सीएनडी वेस्ट फेंकने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए भी कहा है। नगर निगम कमिश्नर शिवम वर्मा ने बुधवार को झोन क्रमांक 3 के विभिन्न क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। वे जेल रोड और नॉवेल्टी क्षेत्र पहुंचे और सफाई व्यवस्था देखी। नॉवेल्टी क्षेत्र की गलियों में कचरा और गंदगी पाए जाने पर रात्रि कालीन सहायक दरोगा जितेंद्र गोड के 5 दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए। इसके बाद कमिश्नर ने जेल रोड डीआरपी लाइन होते हुए लोखंडे ब्रिज तक क्षेत्र का निरीक्षण किया। यहां पर भी निरीक्षण के दौरान सफाई ठीक नहीं पाए जाने पर क्षेत्र के प्रभारी दरोगा संजय टाक का 5 दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं नारायण बाग की गलियों में सीएनडी वेस्ट पड़ा होने पर संबंधित अधिकारियों को सीएनडी वेस्ट फेंकने वालों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। कमिश्नर ने नारायण बाग स्थित प्राचीन बावड़ी का भी अवलोकन किया। कमिश्नर ने तिलक पथ शासकीय 15 नंबर स्कूल के पीछे स्थित मैदान का भी निरीक्षण किया गया। यहां पर जल निकासी के संबंध में निर्देश दिए। सीवरेज संबंधित किए जा रहे निर्माण कार्य का भी अवलोकन किया। निरीक्षण के दौरान अपर आयुक्त सिद्धार्थ जैन, अधीक्षण यंत्री महेश शर्मा, मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉ अखिलेश उपाध्याय, क्षेत्रीय झोनल अधिकारी धीरेंद्र बायस, सीएसआई राम लोवंशी, उप यंत्री राज ठाकुर एवं अन्य उपस्थित थे।

युवती को पिस्टल दिखाकर धमकाया, 4 लाख मांगे, आरोपी पर केस दर्ज

इंदौर। इंदौर के खजराना में रहने वाली 26 साल की युवती को धमकाने का मामला सामने आया है। आरोपी ने पिस्टल दिखाकर पीड़िता से 4 लाख रुपए की डिमांड की। इस मामले में हिंदूवादी नेता की मदद से आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कराया है। खजराना पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक निजी कंपनी में काम करने वाली युवती की शिकायत पर किशोर पुत्र सेवाराम मालवीय निवासी बापू गांधी नगर के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पीड़िता ने बताया कि 10 साल पहले वह पीड़िता की बिल्डिंग में किराये से रहता था। इससे उसकी जान पहचान है। मंगलवार सुबह वह कनाड़िया इलाके में ऑफिस जाने के लिए निकली थी। रिंग रोड स्थित मयूर अस्पताल के यहां वह बाइक लेकर आया और पीड़िता की एक्टिवा के सामने खड़ी कर दी। रास्ता रोककर उसने पिस्टल निकाली ओर धमकाते हुए कहा कि 4 लाख रुपए दे दे। धमकी दी कि रुपए नहीं दिए तो किसी दिन जान से खत्म कर देगा। इसके बाद किशोर वहां से चला गया। परिवार से संपर्क कर रात में हिंदूवादी नेता मानसिंह राजावत के साथ थाने जाकर आरोपी किशोर के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई।

इंदौर पुलिस कमिश्नर राकेश गुप्ता ने इंदौर के आर्ट्स एंड लवर्स कॉलेज में किया दौरा....

14 जुलाई को इंदौर में गृहमंत्री अमित शाह आ रहे हैं इंदौर पुलिस कमिश्नर राकेश गुप्ता ने दी जानकारी...

प्रदीप चौधरी । सिटी चीफ इंदौर। इंदौर पुलिस कमिश्नर राकेश गुप्ता ने मीडिया से चर्चा के दौरान बताया कि इंदौर के आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज में गृहमंत्री अमित शाह 14 जुलाई को इंदौर आ रहा है पौधा रोपण कार्यक्रम में शामिल होंगे तैयारी का जायजा लिया गया है..गृहमंत्री अमित शाह एक पेड़ मां के नाम लगाएंगे कालेज में।

भाजपा नेता दिलीप बुंदेला की हत्या में किसान हिरासत में

इंदौर। इंदौर के पास सिमरोल के जंगल में पूर्व सरपंच के पति का शव सोमवार को मिला था। इस मामले में पुलिस ने उसके साथी तेजू को हिरासत में लिया। तेजू से उसकी आखिरी बार बात हुई थी। उसके पहले संदिग्ध दयाराम ने अपनी पत्नी से कॉल करवाकर सरपंच पति को वहां बुलाया था। सिमरोल थाना इलाके में दिलीप बुंदेला का शव सुरतीपुरा के जंगलों में मिला था। मृतक के शरीर पर कुल्हाड़ी से चार से पांच वार किए गए थे। उन्होंने अपना बचाव भी किया था। जिसमें दो घाव हाथ पर थे। इस मामले में पुलिस ने तेजू नाम के व्यक्ति से पूछताछ की थी। जिसका खेत दिलीप के पास ही था। लेकिन उसके पहले एक और कॉल आया। जिसे पुलिस ने ट्रेस किया और दयाराम भील को हिरासत में लिया। बताया जाता है कि दयाराम ने ही दिलीप की हत्या की है। दयाराम की पत्नी से दिलीप की दोस्ती की बात सामने आ रही है। पुलिस ने अभी इस मामले में किसी तरह का ऑफिशियल बयान जारी नहीं किया है।

रहने के हिसाब से राजधानी भोपाल से बेस्ट है इंदौर...

सिटी चीफ इंदौर।

इंदौर। मध्यप्रदेश के लोग जब किसी जगह बसने की बात करते हैं तो वे भोपाल की अपेक्षा इंदौर को प्राथमिकता देते हैं। दोनों शहरों में रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की संख्या तो कम से कम यही कहती है। एमपी की औद्योगिक राजधानी इंदौर में 2022-23 में राज्य की राजधानी भोपाल की तुलना में तीन गुना अधिक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट रजिस्टर हुईं। यह बताता है कि स्वच्छता लोगों की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इंदौर को लगातार 7वीं बार देश का सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला है। 2022-23 में इंदौर में कुल 258 रियल एस्टेट प्रोजेक्ट रजिस्टर हुईं, जबकि भोपाल में इस साल में 78 प्रोजेक्ट रजिस्टर हुईं। रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण का आकलन है। भोपाल और इंदौर राज्य में रियल एस्टेट विकास के मामले में शीर्ष दो शहर हैं। जबलपुर में 2022-23 में 40 प्रोजेक्ट रजिस्टर हुईं। उज्जैन में 29 प्रोजेक्ट और ग्वालियर में पिछले साल 12 प्रोजेक्ट रजिस्टर हुए। खरगोन ने जबलपुर, उज्जैन और ग्वालियर से अधिक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट रजिस्टर कीं।

जबलपुर, ग्वालियर से आगे खरगोन

खरगोन में 2022-23 में 45 प्रोजेक्ट रजिस्टर हुईं। एमपी में रियल एस्टेट क्षेत्र पिछले वर्षों में बढ़ा है। रेरा के आंकड़े भी यही बताते हैं। रेरा की स्थापना राज्य में 1 मई, 2017 को हुई थी। रेरा, एक सरकारी निकाय, को बिल्डरों या प्रमोटरों और रियल एस्टेट एजेंटों के खिलाफ बढ़ती शिकायतों के कारण स्थापित किया गया था। शिकायतें मुख्य रूप से घर पर देर से कब्जा, समझौते पर साइन करने के बाद प्रमोटरों के गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार और ऐसे ही कई मुद्दों के बारे में थीं।

रियल एस्टेट की बिक्री में धीरे-धीरे सुधार

31 मार्च, 2023 तक रेरा के पास पेंडिंग मामलों की संख्या 846 थी। रियल्टर्स का कहना है कि क्षेत्र में बिक्री नोटबंदी और कोविड-19 के कई वर्षों बाद धीरे-धीरे सामान्य हो रही है। लेकिन रेरा के साथ रजिस्टर प्रोजेक्ट्स की संख्या क्षेत्र के विकास को मापने का एकमात्र मानदंड नहीं था। रेरा के आने के बाद प्रोजेक्ट्स को चरणों में लॉन्च किया जाता है। रियल्टर्स का कहना है कि नए के रूप में गिने जाने वाले प्रोजेक्ट्स में किसी प्रोजेक्ट के नए चरण भी शामिल हैं।

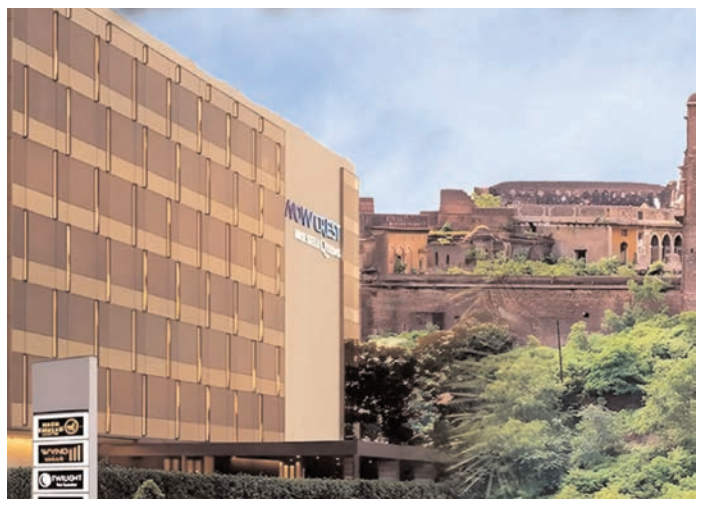

शहरों का मास्टर प्लान भी अब आना चाहिए

रियल्टर्स का कहना है कि त्योहारों के मौसम में बिक्री धीरे-धीरे बढ़ेगी। क्षेत्र को और बेहतर बनाने के लिए आवश्यक कदमों के बारे में विशेषज्ञों ने कहा, राज्य को और अधिक नई प्रोजेक्ट्स की जरूरत है। शहरों का मास्टर प्लान भी अब आना चाहिए ताकि रियल्टर्स को प्रोजेक्ट्स के लिए और जमीन मिल सके। शहरों में मौजूदा लैंड बैंक लगभग खत्म हो गए हैं। जमीन की अनुपलब्धता के कारण कीमतें बढ़ जाती हैं, क्योंकि विकल्प कम हो जाते हैं और मांग बनी ही रहती है।

जीवन यापन का खर्च इंदौर में कम

इंदौर में रहने की लागत आमतौर पर भोपाल की तुलना में कम मानी जाती है। इंदौर में आवास, परिवहन और दैनिक खर्च अधिक किफायती हो सकते हैं।

रोजगार के अवसर इंदौर में ज्यादा

इंदौर बढ़ते औद्योगिक क्षेत्र के साथ एक वाणिज्यिक केंद्र के रूप में जाना जाता है, जो नौकरी के कई अवसर प्रदान करता है। दूसरी ओर, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है और इसमें विभिन्न सरकारी और निजी क्षेत्र के रोजगार के अवसर भी हैं। लेकिन इंदौर की तुलना में भोपाल कम रोजगार के अवसर प्रदान करता है।

शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में दोनों बराबर

दोनों शहरों में अच्छे शैक्षणिक संस्थान और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं हैं। इंदौर कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के साथ अपने शैक्षिक बुनियादी ढांचे के लिए जाना जाता है। भोपाल में गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक और स्वास्थ्य सुविधाएं भी हैं।

परिवहन सुविधाओं इंदौर अधिक विकसित

परिवहन सुविधाओं के मामले में इंदौर को अधिक विकसित माना जाता है। शहर में एक अच्छी तरह से जुड़ी हुई सार्वजनिक परिवहन प्रणाली और अच्छा सड़क नेटवर्क है। भोपाल भी अपने बुनियादी ढांचे में सुधार कर रहा है लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हो सकते हैं जिन्हें और विकास की आवश्यकता है।

55 एक्सीलेंस कॉलेज का शुभारंभ करेंगे अमित शाह

11 लाख पौधे लगाकर बनाएंगे वर्ल्ड रिकॉर्ड

सिटी चीफ इंदौर।

इंदौर/भोपाल। मध्यप्रदेश में 55 एक्सीलेंस कॉलेज का शुभारंभ 14 जुलाई को होगा। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह इंदौर के कार्यक्रम से प्रदेश के सभी जिलों में कॉलेज का शुभारंभ करेंगे। प्रदेश में नई शिक्षा नीति के तहत हर जिले में एक एक्सीलेंस कॉलेज खोला जा रहा है। मध्यप्रदेश शासन के संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि एक्सीलेंस कॉलेज में विषय और रोजगारमूलक शिक्षा दी जाएगी। इन कॉलेजों में प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। केंद्र सरकार की तरफ से प्रत्येक कॉलेज के लिए 22 करोड़ रुपये दिए जा रहे हैं। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर प्रदेश सरकार भी बजट में राशि का प्रावधान करेगी।

भोपाल में कैबिनेट बैठक के बाद म्कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह इंदौर में एक वृहद पौधरोपण अभियान में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि इंदौर में पौधरोपण का कार्यक्रम जारी है। अभी करीब दस लाख पौधे लगाए जा चुके है। इंदौर में 51 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य है। इसमें ही 14 जुलाई को वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा। इसमें एक स्थान पर 11 लाख पौधे लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे। उन्होंने बताया कि यह पौधे 11

घंटे में लगाए जाएंगे। इसके लिए 13 जुलाई से गड्ढे करने का काम शुरू किया जाएगा।

जनभागीदारी से 20 करोड़ पौधे लगाए जाने ह

विजयवर्गीय ने बताया कि पौधारोपण अभियान जनभागीदारी से चलाया जा रहा है। जनभागीदारी से 20 करोड़ पौधे लगाए जाने हैं। इसमें सामाजिक संगठनों को जोड़ा गया है। उन्होंने सामाजिक महापुरुषों के नाम पर वनों के नाम रखे हैं। विजयवर्गीय ने कहा कि मध्यप्रदेश पौधारोपण के मामले में देश में पहला राज्य बनने जा रहा है। इंदौर में हर साल 51 लाख पौधे लगाए जाएंगे।

13 जुलाई की रात से ही शुरू हो जाएगी पौधे लगाने की तैयारी

इंदौर में 14 जुलाई को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की मौजूदगी में एक साथ 11 लाख पौधे लगाकर वर्ल्ड रिकार्ड बनाने की तैयारी की जा रही है। एक साथ 9 लाख पेड़ लगाने का रिकार्ड आसाम के नाम पर है। इसके लिए इंदौर की रेवती रेंज में तैयारियां पूरी हो चुकी है। पौधे लगाने की तैयारी 13 जुलाई की रात से ही शुरू हो जाएगी, लेकिन सूर्यउदय से सूर्य अस्त तक ही लगाए जा सकते है, इसलिए पौधा रोपण सुबह छह से शाम छह बजे तक होगा। टेकरी पर चार फीट से ज्यादा ऊंचाई के पौधे लगाए जाएंगे,ताकि वे जीवित रह सके। जनकार्य समिति प्रभारी राजेंद्र राठौर ने बताया कि 14 जुलाई को रेवती रेज में 70 से 80 हजार लोगों के आने के इंतजाम किए गए है। वहां चार वाटरप्रुफ डोम बनाए जा रहे है। टेकरी पर 11 लाख गड्ढे हो चुके है। शहर के विभिन्न समाजों को पांच से लेकर दस हजार पौधे लगाने की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा अन्य संगठन भी वहां रहेंगे। पौधे लगाने के बाद उन्हें नियमित पानी मिले, इसके लिए वहां बोरिंग भी कराए गए है। 14 जुलाई को दोपहर में गृहमंत्री शाह पौधा लगाएंगे। वे कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। इसके अलावा वे होलकर कॉलेज के एक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे।

पूजा के नाम पर तांत्रिक ने महिला को ठगा

महिला से ठगे 1 लाख 10 हजार रुपए

प्रदीप चौधरी । सिटी चीफ

इंदौर, इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र में एक महिला, प्रेम बाई चंदेल, तांत्रिक की ठगी से परेशान होकर शिकायत दर्ज कराने पहुंची। पीड़िता प्रेम बाई ने बताया कि तांत्रिक संतोष बाबा ने उसके बेटे की पूजा के नाम पर 1 लाख 10 हजार रुपए लेकर ठगी कर ली है। महिला ने अपनी शिकायत में बताया कि वह मूसाखेड़ी में रहती है, जहां संतोष बाबा नाम का तांत्रिक आया और हाथ देखने, नशा छुड़ाने तथा घर की परेशानियों को दूर करने का दावा किया। प्रेम बाई ने बताया कि उनका बेटा जिद्दी है, इसलिए उन्होंने तांत्रिक से पूजन कराने का आग्रह किया। संतोष बाबा ने हवन कराने की बात कही और पहले एक बार नागमणि हवन कराया। इस दौरान, महिला से पूजा की सामग्री के नाम पर पैसे मांगे तो प्रेम बाई ने उसे 7 हजार रुपए दिए। इसके बाद तांत्रिक ने कहा कि माता रानी नहीं मानी हैं। बड़ी पूजा करना पड़ेगी और 2 लाख रुपए पूजा की सामग्री के मांगे जब महिला ने कहा

कि इतने रुपए नहीं हे मेरे पास तब संतोष बाबा ने कुल मिलाकर 1 लाख 10 हजार रुपए लिए और थोड़ी देर में लौटने का कहकर भाग गया। तांत्रिक ने न तो हवन पूरा किया और न ही धूप दी। महिला ने बताया कि संतोष बाबा के फुटेज और डिटेल्स उसके पास हैं। वही जब महिला पुलिस में शिकायत करने एरोड्रम थाने पहुची तो पुलिस कर्मियों ने पीड़ित महिला की रिपोर्ट तक नही लिखी और टेबल पर सोते ही रहे । वही पुलिस के आला अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद माहीला की सुनवाई हो पाई है बहरहाल ठगोरे तांत्रिक बाबा की पुलिस तलाश कर रही है।

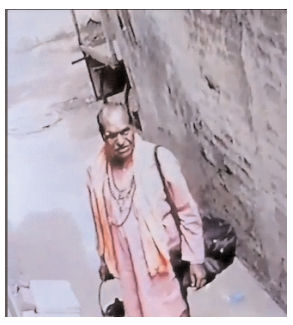

स्कूली वाहनों पर हुई कार्यवाही

20 वाहनों से वसूला 55 हजार रुपये जुर्माना, 02 वाहन जब्त

प्रदीप चौधरी । सिटी चीफ

इंदौर, क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय इंदौर द्वारा लोक परिवहन वाहनों, स्कूली वाहनों सहित अन्य वाहनों की लगातार चेकिंग की जा रही है। जिसमें वाहनों के फ़िटनेश, परमिट, बीमा, PUC, कर प्रमाण पत्र भी चेक किये जा रहे है। बसों में ओवरलोडिंग, अधिक किराया की भी जांच की जा रही है। लोगों को अपने वाहनों पर ॥स्त्रक्क नम्बर प्लेट लगवाने के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है। स्कूल वाहनों की विशेष चेकिंग की जा रही है । जिसमें वाहन की गति, स्पीड गवर्नर सहित दस्तावेज की चेकिंग की जा रही है। बच्चों, पालकों से चालक-परिचालक के व्यवहार के बारे में फीडबैक भी लिया जा रहा है। इस दौरान 20 स्कूल वाहनों सहित अन्य वाहनों पर मोटरयान

अधिनियम की विभिन्न धाराओं में कार्यवाही कर 55 हजार रुपये जुर्माना वसूला गया। मौके पर और ऑनलाइन दस्तावेज नही पाए जाने पर 02 वाहन जब्त भी किये गए।

उज्जैन कलेक्टर को अवमानना मामले में हाईकोर्ट से राहत

सिटी चीफ इंदौर।

इंदौर। उज्जैन कलेक्टर नीरज सिंह को इंदौर हाईकोर्ट की डबल बैंच से राहत मिली है। उनके खिलाफ सिंगल बैंच में अवमानना याचिका लगी थी। जिसमें दोषी करार दिया था। बुधवार को सिंगल बैंच में सजा के प्रश्न पर सुनवाई होनी थी लेकिन अब अगली तारीख 18 जुलाई दी गई है। इस बीच डबल बैंच ने सुनवाई कर ऑर्डर सुरक्षित रख लिया है। बता दें कि जमीन के नामांतरण के एक मामले में उज्जैन कलेक्टर नीरज सिंह सहित मातहतों को अदालत के आदेश का पालन नहीं करना भारी पड़ गया था। आदेश का पालन नहीं करने पर अवमानना दायर की गई थी।

हाईकोर्ट की सिंगल बैंच ने आदेश का पालन नहीं करने पर उन्हें दोषी करार दिया है। बुधवार को हाई कोर्ट को कलेक्टर को सजा के प्रश्न पर सुनवाई करनी थी, जिसमें अगली तारीख 18 जुलाई की दी है।

वहीं कलेक्टर ने सजा से बचने के लिए हाईकोर्ट की डबल बैंच में अपील भी दायर कर दी थी। बुधवार को सुनवाई के बाद ऑर्डर को सुरक्षित रख लिया गया। यही वजह रही की सिंगल बैंच की तरफ से सजा के प्रश्न पर अगली तारीख दे दी गई। अब डबल बैंच की तरफ से ऑर्डर आने के बाद स्थिति साफ होगी। सजा से कलेक्टर को राहत मिलने की संभावना है।

जमीन के नामांतरण का केस

उज्जैन जिले के ग्राम नलखेड़ा के किसान गुलाबचंद प्रजापति की एक जमीन के नामांतरण का केस था। जिसमें मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। हाई कोर्ट में प्रशासन की तरफ से तहसीलदार शैफाली जैन ने कहा था कि नामांतरण प्रक्रिया करेंगे लेकिन इसके बाद भी नहीं की। इसके खिलाफ तहसीलदार शैफाली के साथ ही कलेक्टर नीरज सिंह के खिलाफ अवमानना याचिका दायर हुई। इसमें 31 में 2014 को कोर्ट ने 5 दिन में नामांतरण आदेश दिए। लेकिन नहीं होने पर फिर पीड़ित पक्ष ने जैन और कलेक्टर सिंह के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की। इसमें 3 जुलाई को कोर्ट ने दोनों को 10 जुलाई को व्यक्तिगत पेश होने का आदेश दिया। इस आदेश के खिलाफ कलेक्टर सिंह डबल बैंच में गए थे।

इंदौर के कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में रामायण, महाभारत और गीता की होगी पढ़ाई

सिटी चीफ इंदौर।

इंदौर। इंदौर में विद्यार्थियों को सनातन से जोड़ने की कोशिश शुरू की गई है। दरअसल, इंदौर के जीएसीसी यानी शासकीय अटल बिहारी वाजपेयी कला और वाणिज्य महाविद्यालय के छात्र को वेद पुराण का ज्ञान मिल सकेगा यानी उन्हें रामायण, महाभारत, श्रीमद् भगवद् गीता सहित हर महत्वपूर्ण महाकाव्य, ग्रंथ और साहित्य पढ़ सकेंगे। यह प्रदेश का पहला केंद्र होगा, जहां छात्रों को भारत के महान इतिहास, भारतीय परंपराओं, संस्कृति से अवगत करवाने के लिए सैकड़ों किताबें और लेख होंगे। यहां शिवपुराण, रामचरित मानस सहित भारत के महान इतिहास को दशार्ती किताबें और साहित्य उपलब्ध रहेंगे।

विद्या वन बनेगा, हर छात्र रोपेंगे पौधे

जीएसीसी की खास बात यह है कि यहां विद्या वन भी बनेगा। यहां फर्स्ट ईयर का

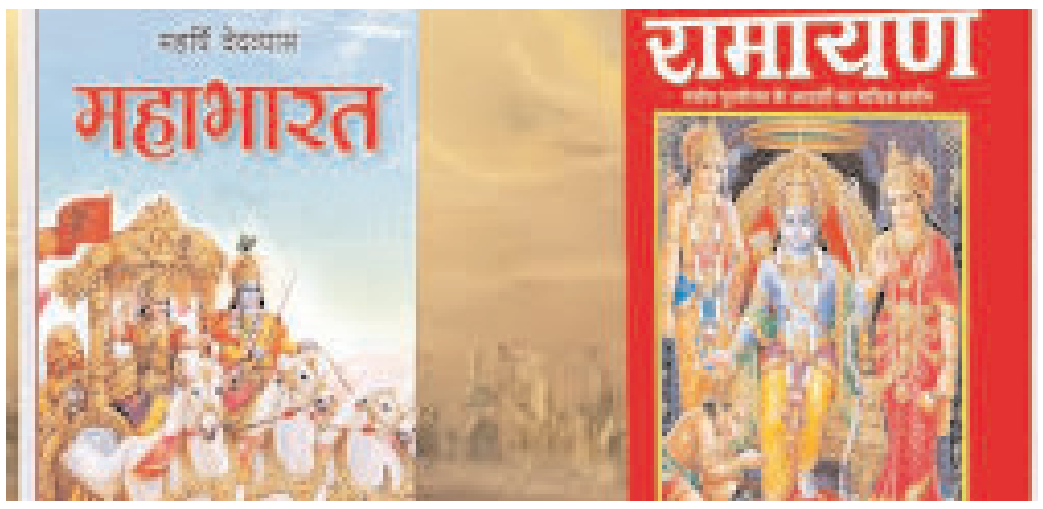

हर छात्र कम से कम एक पौधा रोपेगा और उसे सहेजने का जिम्मा भी उसी का रहेगा। छात्र तीन साल तक अपने लगाए पौधों की देखभाल करेंगे। प्राचार्य डॉ. प्रकाश गर्ग के मुताबिक इस आयोजन को लेकर सभी को अलग-अलग जिम्मेदारी सौंपी है। विद्या वन में छात्र न केवल पौधे लगाएंगे, बल्कि उन्हें सहेजेंगे भी, ताकि छात्र पर्यावरण के प्रति जागरूक हों और जिम्मेदारी की भावना भी जागृत हो सके। यहां हिंदी ग्रंथ अकादमी का विद्यार्थी पुस्तक सहायता केंद्र भी शुरू होगा। यहां छात्रों को साहित्य, कविताएं, लेख, नॉलेज बुक्स, कोर्स की किताबों से लेकर हिंदी और संस्कृत जैसी भाषाओं को मजबूत करने वाले कंटेंट भी मौजूद रहेंगे।

पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ

मध्यप्रदेश के घोषित 55 पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ जीएसीसी में 14 जुलाई को गृह मंत्री शाह करेंगे। इसमें प्रदेश के 54 कॉलेज भी वर्चुअली जुड़ेंगे, जिन्हें पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा मिला है। हर जिले में एक कॉलेज के पास यह दर्जा है। जीएसीसी को कुछ समय पहले पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में शामिल किया गया है। इस दौरान 8 हजार छात्र भी मौजूद रहेंगे, जो शाह के साथ पौधा लगाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी मौजूद रहेंगे।

भोपाल समेत कई जिले तरबतर तो कहीं 37 डिग्री पहुंचा पारा, 16 जिलों के लिए जारी किया अलर्ट

प्रदेश में अभी भी 4 प्रतिशत कम बारिश

सिटी चीफ भोपाल।

मध्य प्रदेश में बुधवार को मौसम मिला-जुला रहा जहां राजधानी भोपाल समेत कई जिलों में बारिश हुई, वहीं कई जिलों का तापमान 37 डिग्री तक पहुंच गया। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में साइक्लोनिक सकुर्लेशन और ट्रफ लाइन के एक्टिव होने से बारिश का दौर जारी है। जारी आंकड़ों के अनुसार बुधवार शाम तक दमोह में सवा इंच और भोपाल में आधा इंच से अधिक पानी गिरा। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में 16 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है।

मध्य प्रदेश मौसम विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में 1 जून से 10 जुलाई 2024 दीर्घावधि औसत से 4त्न कम बारिश हुई है। पूर्वी मध्य प्रदेश में औसत से 16त्न कम जबकि पश्चिमी मध्य प्रदेश औसत से 7त्न अधिक बारिश हुई है। पूर्वी रायसेन, शहडोल,बाणसागर बांध पर तेज बारिश के साथ बिजली गिरने की संभावना है। सीहोर, पश्चिम रायसेन, सागर, दमोह, बैतूल, छिंदवाड़ा, पंढुर्ना,पेंच, देवास, अशोकनगर, शिवपुरी, मुरैना, ग्वालियर, भिंड, सीधी, संजय डुबरी एनपी, दतिया,रतनगढ़, शाजापुर, इंदौर,एपी, बुरहानपुर, पन्ना,टीआर, सतना,चित्रकूट, मैहर, रीवा, मऊगंज, टीकमगढ़, दक्षिण बालाघाट, गुना, राजगढ़ में बिजली गिरने के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। भोपाल,बैरागढ़ एपी, झाबुआ, धार, नीमच, मंदसौर, आगर, खंडवा, हरदा, नर्मदापुरम, श्योपुर, नरसिंहपुर, जबलपुर, डिंडोरी, मंडला, अनूपपुर, उमरिया, छतरपुर, सिंगरौली में शाम के समय बिजली गिरने के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है।

सीनियर मौसम वैज्ञानिक वेद प्रकाश ने बताया कि छतरपुर, पन्ना, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी, धार, रतलाम, झाबुआ, आलीराजपुर, बड़वानी में अगले 24 घंटे में भारी बारिश की संभावना है। उन्होंने बताया कि एमपी के उत्तरी हिस्से में ट्रफ लाइन गुजर रही है। वहीं, साइक्लोनिक सकुर्लेशन भी एक्टिव है। इस वजह से बारिश हो रही है, जो आगे भी जारी रहेगी।

विभिन्न जिलों के ऐसे रहे तापमान

मौसम विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार रीवा और दमोह में पारा 37 डिग्री के पार रहा। सतना, टीकमगढ़, खजुराहो और नौगांव में तापमान 36 डिग्री या इससे ज्यादा दर्ज किया गया। बड़े शहरों की बात करें तो भोपाल में 33.6 डिग्री, इंदौर में 30.8 डिग्री, ग्वालियर में 36.3 डिग्री, जबलपुर में 34.6 डिग्री और उज्जैन में तापमान 33 डिग्री दर्ज किया गया।

नियमानुसार एक प्रमोशन के लिए लगते हैं कम से कम पांच साल, अब 5 साल से चल रही जांच, कार्रवाई नहीं हुई

ईएनसी ऑफिस में 18 महीने में दो बाबुओं को बना दिया अधीक्षक

सिटी चीफ भोपाल।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (पीएचई) विभाग के ईएनसी ऑफिस में कार्यरत दो बाबुओं को नियमों को ताक पर रख कर महज 18 महीने के भीतर ए ग्रेड अधीक्षक बना दिया गया था, जबकि कि नियम के अनुसार एक प्रमोशन के लिए कम से कम पांच साल का समय लगता है। शिकायत के बाद 5 साल से जांच पर जांच चल रही है और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। खास बात यह है कि एक बाबू संदीप सक्सेना का रिटायरमेंट भी हो गया और उन्हें दोबारा संविदा नियुक्ति पर मंत्रालय में पदस्थ कर दिया गया है। वहीं दूसरा बाबू गोपाल खोटपाल अभी भी ईएनसी कार्यालय में काम कर रहे हैं।

जब यह मामला सामने आया तो कुछ कर्मचारियों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। जिसके बाद जांच शुरू हुई और छानबीन कमेटी को तथ्य जांचने कि जिम्मेदारी दी गई, और कमेटी ने अपने रिपोर्ट में शिकायत को सही बताया लेकिन इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। दोबारा से शिकायत हुई तो फिर से निरीक्षण करने के लिए कुछ

अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई। अधिकारियों ने एक माह पहले निरीक्षण करके सीएनसी केके सोनगरिया को रिपोर्ट सौंप दी है लेकिन अभी तक उन्होने कोई निर्णय नहीं लिया है।

18 वरिष्ठों को छोड़कर दिया था प्रमोशन

केके सोनगरिया ने इस मामले में आरटीआई लगाए जाने के बाद इस डीपीसी की जांच के आदेश दिए थे और मामले की जांच के लिए राजेश दुबे को जांच अधिकारी बनाया था। इस मामले में जांच के दौरान पाया गया कि गोविंद खोट पाल को अपने से 18 वरिष्ठों को छोड़कर प्रमोशन दिया गया और इसी आधार पर उन्हें सहायक ग्रेड वन का प्रमोशन भी मिल गया। इसी तरह का मामला संदीप सक्सेना का है जो कि लेखापाल थे और उन्हें प्रमोशन की पात्रता नहीं थी लेकिन तत्कालीन डीपीसी करने वाली कमेटी ने सारे नियमों को ताक में रखकर उन्हें पहले सहायक ग्रेड दो बनाया गया और बाद में सहायक ग्रेड एक के पद पर पदोन्नति दे दी। हैरानी की बात यह है कि यह पदोन्नति एक ही साल में हुई यानी सहायक ग्रेड दो से सहायक ग्रेड वन बनने में दो माह का अंतर है।

सेवानिवृत्ति होने के बाद अब संविदा नियुक्ति

खास बात यह है गोविंद खोटपाल, सदीप सक्सेना की नियम विरुद्ध डीपीसी और सहायक ग्रेड वन तक प्रमोशन देने के मामले की जांच चल रही है और अब संदीप सक्सेना सेवानिवृत्त हो गए हैं, और उन्हें मंत्रालय में संविदा नियुक्ति दोबारा रख लिया गया है। ईएनसी ऑफिस के कर्मचारियों की माने तो गोविंद खोटपाल, सदीप सक्सेना की नियम विरुद्ध डीपीसी और सहायक ग्रेड वन तक प्रमोशन देने के मामले की जांच को प्रभावित करने की कोशिश की गई है।

ईएनसी को सौंप दी है निरीक्षण रिपोर्ट

छानबीन कमेटी द्वारा की गई जांच की रिपोर्ट का पुन निरीक्षण करने वाले मुख्य अभियंता सीके सिंह ने बताया कि हमारा काम रिपोर्ट का निरीक्षण करना था हमने निरीक्षण करके रिपोर्ट ईएनसी केके सोनगरिया को सौंप दी है। कार्रवाई करना या नहीं करना उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। हमारा काम रिपोर्ट का निरीक्षण करना था जो हम ने कर दिया है।

कैबिनेट बैठक में सात सिंचाई परियोजनाओं को मोहन सरकार की मंजूरी

24 करोड़ खर्च करके बनाएंगे पेपरलेस विधानसभा

सिटी चीफ भोपाल।

मध्य प्रदेश की विधानसभा पेपरलेस बनने जा रही है। इस योजना में 60 प्रतिशत लागत का वहन केंद्र सरकार करेगी और राज्य सरकार 40 प्रतिशत खर्च करेगी। इस योजना पर राज्य सरकार के 24 करोड़ रुपये खर्च होना प्रस्तावित है। यह योजना एक साल में पूरी तरह क्रियान्वित हो जाएगी।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि राज्य सरकार ने संसदीय कार्य विभाग के मध्य प्रदेश विधानसभा को पेपरलेस बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

इस पर 24 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। एक साल में प्रोजेक्ट पूरा किया जाएगा। देश की सभी विधानसभाओं को पेपरलेस बनाने और उन्हें एक प्लेटफॉर्म पर लाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन लॉन्च किया है। मध्य प्रदेश की विधानसभा देश की 13वीं विधानसभा होगी, जो पेपरलेस होने जा रही है।

आदिवासी क्षेत्रों में सात सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी

राज्य सरकार ने नर्मदा घाटी विकास विभाग की सात सिंचाई

परियोजनाओं के टेंडर निकालने की अनुमति दी है। नौ हजार 271 करोड़ रुपये की इन परियोजनाओं में सेण्डवा माइक्रो सिंचाई परियोजना, निवाली माइक्रो सिंचाई परियोजना, सेंधवा माइक्रो सिंचाई परियोजना, महेश्वर-जानापाव माइक्रो सिंचाई परियोजना, धार माइक्रो सिंचाई परियोजना शामिल है। यह सभी परियोजनाएं आदिवासी इलाकों में है, जिससे वहां के किसानों को लाभ मिलेगा। इसी तरह कैबिनेट ने सीधी में नई बोकरो माइक्रो सिंचाई परियोजना को भी मंजूरी दे दी है। इस पर 46 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इस परियोजना से 3310 हैक्टेयर की जमीन की सिंचाई हो सकेगी। इसका लाभ रामपुरा नेकिन तहसील के 11 गांवों को मिलेगा।

विमुक्त, घुमन्तु और अर्द्वघुमन्तु कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित छात्रावासों और सामुदायिक केंद्रों में रह रहे छात्र-छात्राओं की छात्रवृत्ति बढ़ाई गई है। अब विभाग के छात्र-छात्राओं को अनुसूचित जाति कल्याण जनजातीय कार्य विभाग से निर्धारित छात्रवृत्ति की दरों में वृद्धि दी जाएगी। बालकों को 1,230 की जगह 1,550 रुपये मिलेंगे। बालिकाओं को 1,270 की जगह अब 1,590 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे।

सांवेर जेल के लिए 217 करोड़ रुपये मंजूर

कैबिनेट ने इंदौर में सांवेर रोड पर निमार्णाधीन केंद्रीय जेल के शेष निर्माण कार्यों के लिए 217 करोड़ रुपये की राशि के लिए प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है।

पति से विवाद के बाद फांसी लगाई

मंत्री पटेल की जनसंपर्क अधिकारी पूजा थापक ने की आत्महत्या

सिटी चीफ भोपाल।

मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग की सहायक संचालक और प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्री प्रहलाद पटेल की सरकारी जनसंपर्क अधिकारी पूजा थापक ने मंगलवार देर रात आत्महत्या कर ली है। 30 वर्षीय पूजा थापक गोविंदपुरा थाना क्षेत्र के साकेत नगर में पति निखिल दुबे के साथ रह रही थीं। पूजा थापक का विवाह दो वर्ष पहले हुआ था। उनके पति निखिल दुबे मध्य प्रदेश सरकार के सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग में सहायक संचालक स्तर के ही अधिकारी हैं। गोविंदपुरा थाना प्रभारी ने बताया कि पूजा थापक ने आत्महत्या की है। उनके पति निखिल और अन्य लोग उन्हें लेकर एम्स अस्पताल पहुंचे थे। इलाज के दौरान पूजा थापक की बीती देर रात मौत हो गई। पूजा थापक का मायका इंदौर के पास है। पुलिस ने साकेत नगर स्थित पूजा थापक के कमरे और निवास की तलाशी ली है, लेकिन वहां से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। पुलिस ने मोबाइल को भी जांच में ले रही है। वर्ष 2022 में दोनों की शादी हुई थी। उनका एक साल का बेटा भी है।

पति से छह माह से हो रहा था विवाद

पुलिस सूत्रों की माने तो पूजा थापक और उनके पति के बीच बीती देर रात साकेत नगर स्थित निवास पर विवाद हुआ। विवाद के बाद पति एक कमरे में चले गए। दूसरे कमरे में पूजा थापक ने जाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या की जानकारी उनके पति को देर रात लगी। वह पड़ोसियों की मदद से पूजा को एम्स ले गए। दोनों में पिछले छह माह से विवाद हो रहे थे। विभाग के अधिकारी और पड़ोसियों को भी दोनों के बीच विवाद होने की जानकारी थी। हालांकि, बीती रात आखिर किस बात पर इतना विवाद हुआ कि एक नवविवाहिता महिला अधिकारी ने फांसी लगाई, पुलिस इसकी जांच में जुटी है।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा- प्रदेश में रोजगार बढ़ रहा, कांग्रेस शासित राज्यों में घट रहा

पीएम का सम्मान 140 करोड़ भारतीय जनता का सम्मान : वीडी

सिटी चीफ भोपाल।

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में बुधवार को पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि आज देश के लिए गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूसी संघ के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह देश की 140 करोड़ जनता का सम्मान है। प्रधानमंत्री मोदी इकलौते प्रधानमंत्री हैं, जिन्हें 15 से अधिक देशों में सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया है,इसमें मुस्लिम देश भी शामिल हैं। शर्मा ने कहा कि कांग्रेस हमेशा प्रदेश में रोजगार को लेकर सवाल खड़ा करती है,लेकिन उसे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) की रिपोर्ट का अध्ययन करना चाहिए, जिसमें मध्य प्रदेश में सात सालों में 6 लाख नौकरियों के बढ़ने की बात कही गई है और रोजगार में 12.2 प्रदिशत की वृद्धि हुई है। ये दशार्ता है कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार के कार्यकाल में मध्यप्रदेश में रोजगार की संभावनाएं लगातार बढ़ रही हैं। सरकार की विभिन्न जनहितैषी योजनाओं व स्टार्टअप को बढ़ावा देने से रोजगार के अवसर खुले हैं।

बैठक का किया बहिष्कार, सीईओ और सदस्यों ने लगाए एक-दूसरे पर आरोप

जिला पंचायत की बैठक में जमकर हुई नारेबाजी-हंगामा

सिटी चीफ भोपाल।

भोपाल जिला पंचायत की कई महत्पूर्ण मुद्दों में बुधवार को होने वाली बैठक नहीं हो पाई बैठक में पहुंचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों ने कहा कि जिला पंचायत सीईओ बैठक में नहीं पहुंचे इसलिए उन्होंने इसका बहिष्कार कर दिया, जबकि सीईओ ऋतुराज ने बताया कि बुधवार को बैठक रखी गई थी लेकिन बैठक के पहले ही राजनीतिक दलों के सदस्य हंगामा करने लगे इसलिए बैठक में वे नहीं पहुंचे। उन्होंने कहा है कि गांवों के विकास में किसी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी।

बुधवार को दोपहर 12 बजे से जिला पंचायत की सामान्य प्रशासन की मीटिंग थी। अध्यक्ष रामकुंवर गुर्जर, उपाध्यक्ष मोहन जाट समेत सभी सदस्य मीटिंग में समय पर पहुंच गए, लेकिन सीईओ ऋतुराज सिंह आधे घंटे बाद तक भी मीटिंग में नहीं पहुंचे। इस वजह से अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों ने मीटिंग का विरोध कर दिया। बहिष्कार करते हुए वह मीटिंग हॉल से बाहर निकल गए। मीटिंग में पानी, स्वास्थ्य, सड़क जैसे कई मुद्दों पर चर्चा होनी था।

सीईओ के खिलाफ निंदा प्रस्ताव

सदस्यों ने बताया कि सीईओ ऋतुराज सिंह के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया गया है। अध्यक्ष ने कहा कि सीईओ किसी की नहीं सुनते हैं। इसलिए निंदा प्रस्ताव लाए हैं। उपाध्यक्ष मोहन जाट ने कहा कि डीईओ एके त्रिपाठी के विरुद्ध पिछली बैठकों में निंदा प्रस्ताव लाए थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए विरोध जताया है। जरूरत पड़ने पर मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे। सदस्यों ने कहा कि जनप्रतिनिधियों के कोई काम नहीं हो रहे हैं। इसलिए यह विरोध किया है। आगे भी यह मुद्दा लेकर जाएंगे।

साधारण सभा की बैठक में भी हुआ जमकर हंगामा

दोपहर 1 बजे साधारण सभा की बैठक में भी जमकर हंगामा हुआ। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित सभी सदस्यों ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कराना चाहते थे। बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा, पीएचई, उद्यानिकी, कृषि, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, प्रधानमंत्री सड़क योजना, पीडब्ल्यूडी, आदिम जाति कल्याण, वन, महिला एवं बाल विकास, मत्योद्योग, पशु चिकित्सा सेवाएं, पंजीयन सहकारी सेवाएं, उप पंजीयक सहकारी समिति, खेल समेत जिपं के अंतर्गत मनरेगा, जल जीवन मिशन, स्वच्छता मिशन, मध्याह्न भोजन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जलगंगा अभियान, पौधारोपण अभियान (एक पेड़ मां के नाम), 15वां वित्त आयोग अंतर्गत वर्ष 2024-24 की कार्ययोजना समेत अन्य विषयों पर चर्चा होनी थी। भोपाल जिला पंचायत वार्ड क्रमांक 10 से सदस्य रश्मि भार्गव ने बताया कि पिछले 6 महीने से बैठक नहीं हुई है, जबकि नियम के अनुसार हर 3 महीने में बैठक होनी चाहिए। बैठक नहीं होने से जनता के काम प्रभावित होते हैं। सभी सदस्य अपने क्षेत्र की सभी समस्याओं को लेकर बैठक में पहुंचते हैं। अब ऐसे में सीईओ द्वारा इस तरह का निर्णय लेना उचित नहीं है। उन्हें बैठक करवानी चाहिए भले ही हंगामा हो रहा था। उन्होंने बताया कि इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होनी थी लेकिन बैठक नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण है।

गांव के विकास से जुड़े कई काम अटके

मीटिंग नहीं होने से गांव के विकास से जुड़े काम अटक गए। सदस्यों का कहना है कि मीटिंग नहीं होने से वे गांव से जुड़े पानी, सड़क, नाला-नाली निर्माण, बिजली कनेक्शन समेत जनता से जुड़े अन्य विषय नहीं उठा पा रहे थे। इसलिए बुधवार को होने वाली मीटिंग में कई मुद्दों पर चर्चा होनी थी।

बतादें कि मीटिंग ही एक ऐसा प्लेटफार्म होता है, जब सभी विभागों के अफसरों से जिपं अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य रूबरू होते हैं। पिछली बैठकों में तो उपाध्यक्ष और सदस्यों की अधिकारियों पर भड़ास भी निकली थी।

सम्पादकीय

देश की बढ़ती जनसंख्या कई चुनौतियां पेश करेगी

11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। यह दिन गर्भनिरोधक और परिवार नियोजन के महत्व को जागरूक करने के लिए समर्पित है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य लोगों को जनसंख्या विस्फोट, परिवार नियोजन, लैंगिक समानता, गरीबी, मातृ स्वास्थ्य और मानव अधिकारों से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना है।

विश्व जनसंख्या दिवस एक महत्वपूर्ण अवसर है जो हमें तेजी से बढ़ती जनसंख्या और उससे जुड़ी चुनौतियों के प्रति जागरूक करता है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन के मुद्दों पर गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है। 2023 के अनुमान के अनुसार, भारत की जनसंख्या 1.4 अरब के करीब है। यह संख्या तेजी से बढ़ रही है। भारत दुनिया के सबसे बड़े और घनी आबादी वाले देशों में से एक है। इसके कारण होने वाली गंभीर स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रतिवर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। यह दिन गर्भनिरोधक और परिवार नियोजन के महत्व को जागरूक करने के लिए समर्पित है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य लोगों को जनसंख्या विस्फोट, परिवार नियोजन, लैंगिक समानता, गरीबी, मातृ स्वास्थ्य और मानव अधिकारों से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना है। विश्व जनसंख्या दिवस की शुरुआत 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा की गई थी।1987 तक दुनिया की जनसंख्या पांच अरब के करीब पहुंच चुकी थी, जिसे लेकर देशों को चिंता होने लगी। इस ऐतिहासिक घटना ने वैश्विक समुदाय का ध्यान तेजी से बढ़ती जनसंख्या और इससे जुड़े मुद्दों की ओर आकर्षित किया। इसके बाद, संयुक्त राष्ट्र ने 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। विश्व जनसंख्या दिवस का मुख्य उद्देश्य परिवार नियोजन के महत्व को जागरूक करना है। सही जानकारी और संसाधनों की मदद से लोग अपनी परिवार की योजना बना सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तेजी से बढ़ती जनसंख्या कई समस्याओं को जन्म देती है, जैसे कि संसाधनों की कमी, पर्यावरण प्रदूषण, और जीवन स्तर में गिरावट। इस दिन का उद्देश्य इन समस्याओं के प्रति लोगों को जागरूक करना और समाधान के उपाय प्रस्तुत करना है।जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन के मुद्दों में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इस दिन महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाता है और उन्हें सशक्त बनाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस का एक और महत्वपूर्ण उद्देश्य मातृ स्वास्थ्य और नवजात स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाना है। उचित स्वास्थ्य सेवाओं की मदद से मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम किया जा सकता है। साल 2011 के बाद से भारत में जनगणना नहीं हुई है इसलिए इस वक़्त भारत की जनसंख्या क्या है, इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी उपलब्ध नहीं है।

लेकिन साल 2020 में नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन ने जनसंख्या के अनुमानों पर एक रिपोर्ट जारी की जिसमें कहा गया कि साल 2011 और 2036 के बीच के 25 साल में भारत की जनसंख्या 121 करोड़ दस लाख से बढ़कर 152 करोड़ 20 लाख हो जाएगी। लेकिन जानकारों का कहना है कि भारत में ज्यादा लोग पहले के मुकाबले लंबी उम्र तक जी रहे हैं और देश में कम बच्चे पैदा हो रहे हैं जिसकी वजह से भारत की जनसंख्या की वृद्धि दर नीचे जा रही है। वृद्धि दर के घटने के बावजूद भारत की जनसंख्या का बढ़ना जारी है और अगले कई सालों तक जारी रहेगा। ऐसी स्थिति में देश के सामने कई चुनौतियां पेश होने की आशंका है। लगातार बढ़ती जनसंख्या की वजह से जो सबसे बड़ी चुनौती पैदा होती है वो है प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ता दबाव। इन प्राकृतिक संसाधनों में जमीन, पानी, जंगल और खनिज शामिल है। जनसंख्या के बढ़ने की वजह से इन संसाधनों का जरुरत से ज्यादा इस्तेमाल होता है। नतीजतन कृषि उत्पादकता और पानी की कमी के साथ पर्यावरण में गिरावट होने की आशंका बढ़ जाती है। बढ़ती आबादी के कारण आवास, परिवहन, स्वास्थ्य और शिक्षण सुविधाओं से जुड़े बुनियादी ढांचे का विस्तार करने की जरूरत भी बढ़ जाती है। एक बहुत बड़ी आबादी की जरूरतों को पूरा करना एक मुश्किल काम बन जाता है और आबादी का एक बड़ा हिस्सा बदहाल हालात में जीने के लिए मजबूर हो सकता है। एक बड़ी आबादी की वजह से काम करने की क्षमता रखने वाले लोगों की एक बड़ी संख्या भी खड़ी हो जाती है। इस बड़ी संख्या को रोजगार उपलब्ध करवाना एक बड़ी चुनौती के तौर पर उभरता है। आज की तारीख में भी भारत में बेरोजगारी एक ज्वलंत समस्या है।

गलती किसी की हो, अपराधी 'पुल' ही होगा...!

बिहार में इतने पुलों के गिरने के बाद भी वहां यह कोई बड़ा राजनीतिक- सामाजिक मुद्दा बनेगा, इसकी कोई संभावना नहीं है। क्योंकि जातिवाद और आरक्षण के आगे वहां सब कुछ गौण है। नीतीश कुमार और उनकी पार्टी चूंकि अब फिर भाजपा के साथ है, इसलिए गिरे पुलों के पुनर्निर्माण के लिए उन्हें केंद्र से पैसा भी आसानी से मिल जाएगा। उनमें से कुछ पुल फिर गिरेंगे और फिर बनेंगे। यह क्रम चलता रहेगा।

पता नहीं बिहार के ही एक जाने माने कवि आलोक रंजन को अपने गृह राज्य में पुलों के धड़ाधड़ गिरने का पूर्वाभास था या नहीं, परंतु टूटे हुए पुल नामक उनकी कविता की ये कुछ पंक्तियां बहुत मौजूं हो उठी हैं-

स्थानीय लोग टूटे हुए
पुल को भी घेर कर खड़े थे
जैसे पुल एक चोटिल अपराधी हो
और दर्द निजाते ही भाग जाएगा...
न पुल टूटने का कोई प्रभाव है या रहेगा
न ही सूरज के डूबने का...
पुल पुराना था
अपनी इस गत का इंतिजार करता
उस के ऊपर ही वह पुल था
जिसने बहुत पहले ही एहसास दिला दिया था कि
मियां दिन पूरे हुए...

वैसे तो इन दिनो देश में घटिया और जल्दबाजी में किए गए निर्माणों तथा उनके उद्घाटनों की राजनीतिक जल्दबाजी के चलते पुलों, इमारतों, छज्जों के गिरने, ध्वस्त होने और ऐसे अप्रत्याशित हादसों में जान गंवाने की घटनाएं अचानक से बढ़ गई हैं, लेकिन बिहार में जिस तरह एक माह से भी कम समय में विभिन्न नदी-नालों पर बने 13 पुल पुलिया गिरी हैं या गिर रही है, वह यही साबित करता है कि राज्य भ्रष्टाचार के पुल असली पुलों के मुकाबिल बहुत ज्यादा मजबूत हैं। ऐसे पुल, जिनके ध्वस्त होते जाने को लेकर किसी के माथे पर खास शिकन नहीं है। यानी पुल ही तो था, जो गिर गया। अब क्या करें का भाव।

इसको लेकर मीडिया में बहुत हल्ला हुआ तो राज्य की नीतीश सरकार ने 15 इंजीनियरों को सस्पेंड कर दिया। ठेकेदारों पर कार्रवाई की बात भी कही जा रही है। चूंकि बिहार में नीतीश सरकार कपड़ों की मानिंद अपना आवरण बदलती है, इसलिए सभी पार्टियां घटिया पुल निर्माण के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार बता रही हैं। इसमें भी यह सावधानी बरती जा रही है कि उसी पुल के बारे में सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाए, जिस वक्त आरोपी पार्टी सत्ता में रही हो।

इस बीच राज्य सरकार ने गिरे हुए पुलों को फिर से बनाने का आदेश दे दिया है। बने अथवा निर्माणाधीन पुल क्यों गिर गए, इसकी जांच चलती रहेगी। मजबूर बिहारवासी फिर नावों के सहारे या तैर कर नदियां पार कर रहे हैं और अपनी किस्मत को कोस रहे हैं। दूसरी तरफ गैर बिहारवासियों के मन में खौफ समा गया है बिहार से गुजरना खतरे से खाली नहीं है। न जाने कौन सा पुल कब धंस जाए और कोई यात्रा अंतिम यात्रा में बदल जाए।

इस देश में प्राकृतिक आपदा, घटिया निर्माण, गलत डिजाइन आदि के चलते पुलों, भवनों का गिरना कोई नई बात नहीं है। दूसरे राज्यों में भी ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। क्योंकि निर्माण के हर टेंडर में भ्रष्टाचार एक अलिखित लेकिन अनिवार्य शर्त होती है, जो सार्वजनीक है। फर्क सिर्फ इतना होता है कई जगह भ्रष्टाचार और कमीशनबाजी की लक्ष्मण रेखा के परे एक लोकलाज की अदृश्य रेखा भी होती है, जिसे ध्यान में रखकर इतनी सावधानी बरतने की कोशिश होती है कि सिर मुंडाते ही ओले न पड़ जाएं। ऐसे में बहुत सी इमारते और पुल निर्माण के कुछ बरस बाद टूटकर व्यवस्था पर भरोसा कायम रखते हैं।

टूटने या गिरने की स्थिति में उनके उम्रदराज होने का वाजिब कारण बताया जा सकता है। अलबत्ता बिहार में जो पुल गिरे हैं, वो तो बाल्यावस्था से लेकर जवानी में ही दम तोड़ रहे हैं। ऐसी इक्का-दुक्का घटनाएं पहले भी होती रही हैं, लेकिन पुल ध्वस्तीकरण का यह अटूट सिलसिला राज्य में पिछले माह 18 जून से शुरू हुआ, जहां 7 जुलाई तक 13 पुल दम तोड़ चुके थे। टूटने वाली तेरहवीं एक पुलिया है। इस क्रम में गिरने वाला पहला पुल राज्य के अररिया जिले के सिकटी प्रखंड में था।

इसके भी पहले इसी साल मार्च के महीने में सुपौल जिले में कोसी नदी पर बन रहे पुल का एक हिस्सा गिरा था। इस हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई थी, जबकि 10 अन्य घायल हुए थे। इसी तरह बिहार में पिछले साल गंगा नदी पर बन रहे पुल का एक हिस्सा गिर गया था। यह पुल करीब 1 हजार 717 करोड़ की लागत से भागलपुर जिले के सुल्तानगंज और खगड़िया जिले के अगुवानी नाम की जगह के बीच बन रहा था। पुल गिरने की इस तस्वीर को बड़ी संख्या में लोगों ने सोशल मीडिया पर साझा किया था और सरकार ने जांच के आदेश भी दिए थे। आगे क्या हुआ किसी को नहीं पता।

यूं भारत में पुलों के बनने और उनके गिरते जाने का अपना इतिहास है, जो देश के सामाजिक और राजनीतिक ताने- बाने के बनने और बिगड़ने के समांतर निर्विकार भाव से चलता रहता है। यह भी हकीकत है कि आज देश में कई पुल ऐसे भी हैं, जो अंग्रेजों के जमाने के हैं, लेकिन उम्र ढलने के बाद भी यातायात का बोझा ढो रहे हैं। पुल ध्वस्तीकरण की बात करें तो आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक भारत में 2012 से 2022 के बीच 285 पुल ध्वस्त हुए, जिसमें 2022 गुजरात के मोरबी में मच्छु नदी पर बना पुल टूटने से 141 लोगों की मौत का भीषण हादसा भी शामिल है।

यूं पुल निर्माण में जोड़ने का भाव निहित है। दूरियां कम करके यातायात और सामाजिक आर्थिक संपर्कों को सुगम बनाने का उपक्रम है। पुल अपने आप में रचनात्मकता और सौहार्द का प्रतीक हैं। नार्वे के नोबेल विजेता वैज्ञानिक और मानवतावादी फ्रिजॉफ नानसेन ने कहा था कि मैं अपने पीछे उस पुल को ढहा दूंगा ताकि आगे बढ़ने के अलावा कोई रास्ता न बचे। यानी पुल पीछे लौटने का नहीं, आगे बढ़ने का रास्ता है। लेकिन भारत में पुल देश को पीछे भी ले जाते हैं। हमारे यहां मानो पुल की परिभाषा केवल रेत सीमेंट की ऐसी संरचनाओं से है, जिसकी आत्मा को करप्शन ने पहले ही लील लिया होता है।

पुल आखिर गिर क्यों जाते हैं? विशेषज्ञ इसका पहला कारण तो प्राकृतिक आपदा को मानते हैं, जिसके आगे इंसान का कोई बस नहीं। इसे अलग रखें तो गलत डिजाइन, लापरवाही, उम्र से ज्यादा समय तक इस्तेमाल, प्राकृतिक आपदा, घटिया सामग्री का इस्तेमाल, ओवर लोडिंग या फिर मानव निर्मित आपदाएं जैसे कि बेजा रेत खनन या लापरवाही से किया गया नदी का गहरीकरण, नदी की प्रकृति की अनदेखी आदि। वैसे भारत में एक पुल की औसत आयु 34.5 साल मानी गई है। लेकिन हमारे यहां पुलों की शिशु मृत्यु दर भी कम नहीं है।

यहां तर्क दिया जा सकता है कि भारत में जितनी बड़ी तादाद में पुल-पुलिया बने हैं, उनके अनुपात में गिरने वाले पुल- पुलियाओं की संख्या बहुत कम है। अगर भारतीय पुल प्रबंध प्रणाली (आईबीएमएस) के आंकड़ों को देखें तो भारत में नेशनल हाइवे पर कुल 1 लाख 17 हजार 517 पुल- पुलिया हैं। इनमे 30 फीसदी पुलिया, 15 फीसदी छोटे पुल 8.1 प्रतिशत बड़े पुल तथा 5 फीसदी ज्यादा लंबे पुल खराब हालत में हैं। जबकि इनमें से असमय गिरने वाले पुलों की संख्या बहुत कम है।

लिहाजा भारत को गिरते पुलों का देश कहना ठीक नहीं है। पर इसी के साथ यह सवाल भी नत्थी है कि पुलो के गिरने में बिहार ही देश की राजधानी क्यों बना हुआ है? इसके निश्चित कारण शायद किसी जांच रिपोर्ट में सामने आएं, लेकिन एक बात मोटे तौर पर साफ है, वह है राज्य में गुणवत्ता की जगह कम लागत पर जोर। कम लागत में से भी जरूरी कमीशन को और कम कर दें तो निर्माण पर होने वाला वास्तविक खर्च खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। स्वयं को गरीब और पिछड़ा राज्य कहलाने और उसी खुमारी में जीते रहने का यह आत्मसंतोषी बहाना है। यानी लोगों की जान और टिकाऊपन से ज्यादा अहम है सस्ता होना।

अगर यही फार्मूला हकीकत है तो सस्ता रोए बार बार वाली कहावत यूं ही नहीं बनी है। बिहार में इतने पुलों के गिरने के बाद भी वहां यह कोई बड़ा राजनीतिक-सामाजिक मुद्दा बनेगा, इसकी कोई संभावना नहीं है। क्योंकि जातिवाद और आरक्षण के आगे वहां सब कुछ गौण है। नीतीश कुमार और उनकी पार्टी चूंकि अब फिर भाजपा के साथ है, इसलिए गिरे पुलों के पुनर्निर्माण के लिए उन्हें केंद्र से पैसा भी आसानी से मिल जाएगा। उनमें से कुछ पुल फिर गिरेंगे और फिर बनेंगे। यह क्रम चलता रहेगा।

कुल मिलाकर बिहार पुल की स्थापित परिभाषा को अपने हिसाब से बदलता रहेगा। दूसरी तरफ बिहार की जनता टूटते पुलों के बीच अपना वजूद बचाने के लिए संघर्ष करती रहेगी। गलती किसी की भी हो, अपराधी पुल ही होगा। किसी शायर ने ठीक ही कहा है- सुना है तारीफों के पुल के नीचे, मतलब की नदी बहती है।

चुनौतियों के बीच बेहतर कर प्रशासन के अवसर पहचानना जरूरी, तर्कसंगत बनेगी व्यवस्था

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) भारतीय कराधान के इतिहास में एक ऐतिहासिक कर सुधार रहा है। यह अब सात साल पुराना हो चुका है। एक जुलाई, 2017 को शुरू होने के बाद से इसे लेकर उम्मीदें बढ़ी ही हैं। जीएसटी का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसने कर व्यवस्था को अधिक कुशल और सरल बना दिया है। हालांकि विभिन्न संक्रमणकालीन चुनौतियों के कारण थोड़ा संदेह भी पैदा हुआ है।

अप्रत्यक्ष कर पारंपरिक रूप से सरकारों के लिए कर राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत रहा है। लंबे समय तक अप्रत्यक्ष कर को राजस्व के साधन के रूप में देखा जाता था, न कि आर्थिक विकास को बढ़ावा देने वाले साधन के रूप में। नतीजतन लंबे समय तक यह पुराने ढंग से चलता रहा, जिसमें कोई सुधार न हुआ। 1970 के दशक के बाद गठित विभिन्न समितियों ने इनमें व्यापक सुधार की सिफारिश की, जिनमें से कुछ को लागू किया गया। बाद में अप्रत्यक्ष कर में कई बदलाव हुए, जो अंतत: 2005 में मूल्य वर्द्धित कर (वैट) के रूप में सामने आए। जीएसटी उसी वैट प्रणाली का विस्तार है। जीएसटी में तकनीक का भी व्यापक उपयोग किया गया है। पूरा जीएसटी नेटवर्क इस पर निर्भर है। ई-वे बिल इस तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि यह वस्तुओं की आवाजाही को कर प्रशासन की नजर में रखता है। इसके अलावा ये बिल आपूर्तिकर्ताओं के जीएसटी रिटर्न में स्वत: शामिल हो जाते हैं, जिन्हें पहले मैनुअली जांचना पड़ता था। चूंकि अब सब कुछ ऑनलाइन है, तथा ई-वे बिल का प्रारूप पूरे देश में एक जैसा है, इसलिए पारगमन दस्तावेजों की जांच में लगने वाला समय घट जाता है तथा विभिन्न राज्यों में अलग-अलग प्रक्रियाओं से पैदा होने वाली उलझन भी खत्म हो जाती है।

जीएसटी का एक लाभ यह भी है कि इससे क्षेत्रीय असमानताएं धीरे-धीरे कम हो रही हैं। चूंकि पहले ज्यादातर कर उत्पादन के आधार पर थे, इसलिए कर राजस्व का ज्यादा हिस्सा उत्पादक राज्यों द्वारा अर्जित किया जाता था। अब चूंकि जीएसटी गंतव्य पर आधारित है, इसलिए कर राजस्व उन राज्यों को मिलता है, जहां उपभोग होता है। इससे उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश जैसे गरीब, उपभोक्ता राज्यों को मदद मिलती है। हालांकि जिन राज्यों को इससे राजस्व में हानि की आशंका थी, उन्हें केंद्र सरकार ने पांच साल तक मुआवजा दिया। मुआवजा बंद करने के बाद भी राज्यों के राजस्व में कोई बड़ी कमी नहीं हुई। मतलब जीएसटी राजस्व राज्यों में सुव्यवस्थित हो गया है।

हालांकि, भारतीय जीएसटी एक ऐसा मॉडल है, जो इतने बड़े कर सुधार की जटिलताओं और उनके बाद के समाधान को दर्शाता है। फिर भी कर ढांचे के कुछ पहलू जीएसटी की सरलता के वादों के विपरीत हैं।

संतुलन समय की जरूरत, प्राकृतिक रूप से संतानोत्पत्ति भविष्य के लिए आवश्यक

पिछले कुछ वर्षों में हर?ओर आईवीएफ या आम भाषा में टेस्ट ट्यूब बेबी की छोटे-बड़े शहरों में हो रही वृद्धि, घटती प्रजनन दर, शहरी युवा विशेष तौर पर व्यावसायिक शिक्षा में दक्ष पीढ़ी की संतानोत्पत्ति के प्रति निरंतर बढ़ती अरुचि भविष्य के लिए शुभ संकेत नहीं है। मोटे अनुमान के अनुसार, दस वर्ष के भीतर भारत में आईवीएफ उद्योग लगभग पांच गुना?वृद्धि के साथ 370 करोड़ डॉलर के बराबर हो जाएगा, जो 2020 में 80 करोड़ डॉलर से भी कम था। इन तथ्यों से यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि प्रजनन क्षमता में कमी आ रही है, बल्कि इसकी पृष्ठभूमि में संतानोत्पत्ति के प्रति बढ़ती अरुचि है। कॅरिअर के कारण बच्चे पैदा करना अभिजात्य वर्ग की प्राथमिकता में लगभग अंतिम छोर पर पहुंच गया है। इस प्रकार एक नए समाज की संरचना हो रही है। इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र ने विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर उपेक्षित एवं वंचित वर्ग संबंधी गणना तथा आंकड़ों के वैज्ञानिक संग्रहण को अपना लक्ष्य बनाया है। यह चौंकाने वाला है, क्योंकि विगत 30 वर्षों से 11 जुलाई (विश्व जनसंख्या दिवस) को जनसंख्या संबंधी बड़े-बड़े आयोजनों में नए विषयों के प्रति संकल्प लिए जाते रहे हैं। इनमें वंचित वर्ग उपेक्षित ही रह जाता था। लेकिन अब संयुक्त राष्ट्र को उसका ख्याल आया है।

इसके पीछे वर्तमान संदर्भ और भविष्य की जनसंख्या संबंधी कुछ अनुमान हैं। उपलब्ध अनुमानों के अनुसार, अगले पच्चीस वर्षों में दुनिया के मात्र एक तिहाई देशों (204 में से 49 देशों) में ही पर्याप्त प्रजनन दर रहेगी, जो इस शताब्दी के अंत तक मात्र तीन प्रतिशत यानी 204 में से छह राष्ट्रों तक सिमट कर रह जाएगी। अनुमान के अनुसार, आबादी में वृद्धि मुख्यत: अफ्रीकी देशों में होगी। माना जाता है कि शताब्दी के अंत तक आधी आबादी अफ्रीकी राष्ट्रों में पैदा होगी।

इसके साथ ही प्रजनन की प्रवृत्ति मूलत: निम्न मध्यवर्ग तक सीमित रह जाएगी, जिससे भविष्य में व्यापक वर्गभेद होने की आशंका है, क्योंकि आबादी में निम्न आय वर्ग की संतानों की बहुतायत होने तथा उच्च वर्ग में संतानोत्पत्ति से बेरुखी होने के कारण उपलब्ध संसाधनों पर धीरे-धीरे नियंत्रण बदल जाएगा, जो अभिजात्य वर्ग को मंजूर नहीं हो सकता है। विडंबना यह होगी कि सामर्थ्यवान के पास संतान नहीं और संतान वाले के पास संसाधन नहीं। आशंका यह भी है कि प्रजनन के अभाव में अनेकानेक विकसित राष्ट्रों में अप्रवासी और शरणार्थी भारी संख्या में प्रवेश करेंगे।

जनसंख्या असंतुलन का एक विशिष्ट उदाहरण है दक्षिण कोरिया और नाइजीरिया की वर्तमान स्थिति। पिछले कुछ वर्षों में जहां दक्षिणी कोरिया में ऋणात्मक प्रजनन दर रही है, वहीं नाइजीरिया में प्रजनन दर लगभग प्रति महिला सात बच्चों की पाई गई है। ऐसे में संसाधनों का पुन: बंटवारा होना लाजिमी है। कोरिया की महिलाएं अपने व्यावसायिक जीवन की उन्नति और बच्चों के लालन-पालन की बढ़ती लागत के कारण संतान देर से या नहीं पैदा करती हैं। इस ऋणात्मक वृद्धि के कारण सृष्टि पर कई विषम प्रभाव भी पड़ेंगे।

सामान्य तौर पर तो आबादी की कमी से सहज एवं सुगम जीवन की प्रत्याशा रहती है, किंतु इस कमी के कारण किंचित महत्वपूर्ण व्यवसाय यथा कृषि अत्यधिक प्रभावित होंगे, जिससे खाद्य सुरक्षा, पर्यावरण आदि पर असर पड़ेगा। कम आबादी से लोगों का व्यावसायिक रुझान श्रम विहीन, तकनीकी कौशल, शोध आदि की ओर होगा। आशंका है कि घटती आबादी भ-ूराजनीतिक सुरक्षा संबंधी चुनौतियों को भी जन्म देंगी। इसी कारण 1994 में जनसंख्या वृद्धि को 2.1 बच्चे प्रति महिला तक सीमित करने का लक्ष्य तय किया गया था, ताकि संतुलन कायम हो सके। वर्तमान परिदृश्य भविष्य में असंतुलन की आशंका को दर्शाता है।

भारत में भी जनसंख्या स्थिरीकरण एक गंभीर चुनौती है। औसत आयु में वृद्धि, बेहतर चिकित्सा सुविधाओं, संसाधनों की उपलब्धता के चलते अगले कुछ वर्षों में संख्यात्मक वृद्धि तो दिखेगी, किंतु वास्तविक रूप में प्रजनन दर निरंतर घटती जा रही है। आशंका है कि शताब्दी के अंत तक प्रजनन दर मात्र एक बच्चा प्रति महिला तक सीमित हो जाएगी। अत: आवश्यक है कि आबादी का गुणावगुण के आधार पर विश्लेषण हो न कि महज जनसंख्या को बोझ मानकर। संतुलन समय की आवश्यकता है, तो प्राकृतिक रूप से संतानोत्पत्ति को कायम रखना भविष्य की आवश्यकता।

जिले में 113 लेखपालों को नियुक्ति पत्रों का किया गया वितरण

कार्यक्रम का हुआ सजीव प्रसारण

जिला पंचायत अध्यक्ष और जिलाधिकारी ने नव नियुक्त लेखपालों को दायित्व निर्वहन के लिए कराया कर्तव्यबोध

गौरव सिंघल । सिटी चीफ ।

सहारनपुर, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ द्वारा लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में मिशन रोजगार के तहत उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा निष्पक्ष एवं पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के तहत 7720 पदों पर चयनित लेखपालों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गये। लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम का पाईनवुड ऑडिटोरियम में सजीव प्रसारण किया गया। कार्यक्रम में जनपद की पांचों तहसीलों के 113 नव नियुक्त लेखपालों को जिला पंचायत अध्यक्ष, जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी प्रशासन द्वारा नियुक्ति पत्रों का वितरण किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी अलग-अलग जनपदों में चयनित युवा प्रतिभाओं को प्रदेश की सेवा में आने के लिए शुभकामनाएं देते हुए परिजनों को बधाई दी। उन्होंने चयनित 7720 लेखपालों को उनके कर्तव्यों के प्रति आगाह किया। उन्होंने कहा कि ये नियुक्ति प्रक्रिया पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ संपन्न हुई है। इसमें कहीं कोई भेदभाव नहीं हुआ, कोई सिफारिश की आवश्यकता नहीं पड़ी। ऐसे में ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि बिना किसी सिफारिश के प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ ही एक गरीब की ईज ऑफ लिविंग के लिए आपको अपने स्तर पर विशेष कार्य करना है। एक गरीब के जीवन के लिए आपकी ऊर्जा और प्रतिभा लगे, निवेश की संभावनाओं में आपका सकारात्मक सहयोग मिले। जाति, निवास, आय प्रमाणपत्र के लिए जो समय सीमा तय की गई है उसके अनुसार आम जनमानस और युवाओं को सहयोग प्राप्त हो। वरासत, नामांतरण और पैमाइश से जुड़ी कार्यवाही समय से पूरी हों। लोगों के बीच में आपकी अच्छी छवि बने। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा पिछले 7 वर्षों से नियुक्ति प्रक्रिया निष्पक्ष रूप से चल रही है। इसकी वजह से 6 लाख से ज्यादा युवा प्रदेश की उन्नति मे सहयोग दे रहे है। पुलिस विभाग में ही अकेले एक लाख 55 हजार युवा भर्ती किए गए। अब बिना भेदभाव और आरक्षण नियमों का पालन करते हुए युवा योग्यता के

अनुरूप भर्ती हो रहे हैं। नियुक्ति प्रक्रिया में निष्पक्षता से युवाओ में विश्वास आया है। युवाओं का विश्वास ही हमारी ताकत है। उन्होंने कहा प्रदेश में युवा का सम्मान होता है। अध्यक्ष जिला पंचायत मांगेराम चौधरी ने चयनित लेखपालों को बधाई देते हुए कहा कि वर्तमान में सभी को योग्यता के आधार पर रोजगार मिल रहा है। पूर्ण पारदर्शिता के साथ नियुक्ति पत्र वितरित किए जा रहे हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि नव चयनित युवा अपने विभागीय दायित्वों का बखूबी निर्वहन करेंगे और अपने दायित्वों को निष्पक्षता के साथ पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी से निभाएंगे। जिलाधिकारी मनीष बंसल ने सभी नव नियुक्त लेखपालों को बधाई एवं शुभकामनाएं देने के साथ ही उन्हे कर्तव्यबोध कराते हुए कहा कि लेखपाल राजस्व विभाग के साथ-साथ सम्पूर्ण प्रशासनिक ढांचे की नींव एवं महत्वपूर्ण कडी है इसलिए अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए संवेदनशीलता एवं मेहनत के साथ कार्य करें। राजस्व से संबंधित अधिनियमों एवं नियमावलियों का गहनता से अध्ययन करते हुए शासन एवं प्रशासन की अपेक्षानुसार नियमों के दायरे में रहते हुए कार्य करें। अपने शुरूआती कार्यकाल में उत्सुकता के साथ कार्य करें। समस्या आने पर अपने वरिष्ठ अधिकारियों से मार्गदर्शन लें। उन्होने कहा कि समस्याओं को टालना नहीं है बल्कि उनका समाधान निकालना है। सभी लेखपाल अपने-अपने नियुक्ति क्षेत्र में भ्रमण करते रहें एवं निरंतर लोगों के सम्पर्क में रहें। आमजन की समस्याओं का निष्पक्षता, ईमानदारी और संवेदनशीलता के साथ निस्तारण करें। विकास एवं जन कल्याण संबंधी योजनाओं के क्रियान्वयन में अपनी अहम भूमिका निभाएं जिससे अधिक से अधिक पात्रों को योजनाओं का लाभ मिल सके। इस अवसर पर प्रतिनिधि राज्यमंत्री संसदीय कार्य एवं औद्योगिक विकास कृष्ण सैनी, अपर जिलाधिकारी प्रशासन डॉ0 अर्चना द्विवेदी, समस्त उपजिलाधिकारी एवं तहसीलदार तथा नव नियुक्त लेखपाल एवं उनके परिजन उपस्थित रहे।

लक्ष्य के अनुरूप शत-प्रतिशत करें राजस्व वसूली :- जिलाधिकारी मनीष बंसल

जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कर-करेत्तर एवं राजस्व वसूली की समीक्षा बैठक संपन्न

गौरव सिंघल । सिटी चीफ ।

सहारनपुर, जिलाधिकारी मनीष बंसल की अध्यक्षता में कलैक्ट्रेट सभागार में कर-करेत्तर एवं राजस्व कार्यों की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में डीएम मनीष बंसल ने कहा कि विकास एवं निर्माण कार्यों को सतत् रूप से जारी रखने के लिए विभिन्न माध्यमों से प्राप्त होने वाले राजस्व की शत-प्रतिशत वसूली की जाए। डीएम ने भू राजस्व, परिवहन, स्टांप, वन, आबकारी, खनिज, नगर निकाय, कृषि, लोक निर्माण विभाग, वाणिज्य कर, मंडी, बांट माप, विद्युत एवं अन्य विभिन्न विभागों के लक्ष्य के सापेक्ष वसूली की समीक्षा करते हुए कहा कि जो शासन द्वारा लक्ष्य निर्धारित किया गया है उसी के सापेक्ष सभी विभाग प्रगति प्राप्त करें। उन्होंने उप जिलाधिकारियों

से कहा कि विद्युत की आरसी वसूली शत-प्रतिशत सुनिश्चित कराएं। तहसीलदार वसूली पर विशेष ध्यान दें। उन्होंने उप जिलाधिकारियों एवं तहसीलदारों को निर्देशित किया कि राजस्व वादों में दायरे के अनुसार निस्तारण सुनिश्चित कराएं। साथ ही पुराने वादों का निस्तारण सुनिश्चित कराएं।

जिलाधिकारी मनीष बंसल ने वाणिज्य कर एवं विद्युत की कम वसूली होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि विद्युत चोरी करने वालो को चिन्हित कर पुलिस प्रशासन से सहयोग लेकर कार्यवाही की जाए। वाणिज्य कर को निर्देश देते हुए कहा कि सीमावर्ती जिलों के बॉर्डर पर चेकिंग बढ़ाई जाए। सभी तहसीलदारों को निर्देशित किया कि समय सीमा निर्धारित कर आरसी का मिलान कर विसंगतियां दूर करें। परिवहन विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रवर्तन की प्रभावी कार्यवाही की जाए। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन डॉक्टर अर्चना द्विवेदी, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व रजनीश कुमार मिश्र, अपर जिलाधिकारी न्यायिक रमेश यादव, समस्त एसडीएम एवं तहसीलदार सहित संबंधित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे।

डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, हाथी पांव जैसे रोगों से कैसे बचें!

मच्छरों के लार्वा को समाप्त करने के लिये घरों में पानी में सरसों तेल एक ढक्कन डाल दें - डॉ डीके शर्मा

आदित्य द्विवेदी । सिटी चीफ ।

भिंड, भिंड के जिला मलेरिया अधिकारी डॉ डीके शर्मा ने आज एक प्रेस वार्ता कर बताया कि मलेरिया को कैसे रोका जा सकता है डॉक्टर डीके शर्मा ने कहा कि अपने आसपास खास खाली प्लाटों एवं सड़कों पर जो पानी एकत्रित हो जाता है अगर हो सके तो उसे पानी को या तो निकाल देंअगर छोटा गड्ढा है तो उसमें मिट्टी डाल दें ताकि वह लेवल हो जाए और पानी न भर सके ठहरे हुए पानी में ही मच्छर है जो अपना लार्वा छोड़ता है और उससे डेंगू चिकनगुनिया हाथी पांव मलेरिया जैसी गंभीर बीमारियां फैलती हैं साथ ही डॉक्टर डीके शर्मा ने बताया कि अपने घरों में भी जो कलर है उनके पानी को 1से 2 दिन में बदलना चाहिए और जो इस्तेमाल होने वाला पानी ड्राम में भरकर

रख दिया जाता है तो उसे पानी को भी तीन से चार दिन में बदल देना चाहिए या फिर किसी कपड़े से उस ड्रम को ढक देना चाहिए ताकि मच्छर अपना लार्वा उसे पानी में ना छोड़ सके इससे जब लार्वा नहीं छूटेगा तो फिर डेंगू चिकनगुनिया हाथी भाव मलेरिया जैसी बीमारियां भी नहीं होगी साथ ही डॉक्टर डीके शर्मा ने यह भी बताया कि भिंड शहर अंचल के सभी वार्डों में हमारी टीम जाकर सर्वे कर रही है और भिंड जिले के सभी ग्राम पंचायत में भी हमारी टीम ज्यादा कर सर्वे कर रही है जहां भी लार्वा मिलता है उसे नष्ट करने का काम किया जा रहा है

सभी तहसील कार्यालयों में जनसुनवाई के संबंध में सूचना चस्पा करवाई जाए

6 माह से पुरानी जनसुनवाई शिकायतो को अगले 3 दिवसों में प्राथमिकता से निराकृत करें

नर्मदापुरम

आपदा प्रबंधन के लिए पुनर्वास केंद्रों पर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध रहे

सुशासन के संबंध में शासन के निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करे सभी विभाग - कलेक्टर

समय सीमा बैठक आयोजित

बुधवार को कलेक्टर कार्यालय में कलेक्टर सोनिया मीना की अध्यक्षता में समय सीमा की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कलेक्टर द्वारा जनसुनवाई, सीएम हेल्पलाइन, आदि विषयों पर विस्तार से समीक्षा की। कलेक्टर ने सभी तहसीलदारों को निर्देशित किया है कि अपनी अपनी तहसील कार्यालय में जनसुनवाई के संबंध में सूचना चस्पा करवाए तथा ब्लॉक लेवल पर भी जनसुनवाई चालू करें जिससे लोगों को अनावश्यक जिला मुख्यालय आकर परेशान ना होना पड़े। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि शिकायतों के निराकरण में किसी भी प्रकार की कोताही न बरती जाए। उन्होंने 6 माह से अधिक पुरानी जनसुनवाई के लंबित प्रक्रणो के लिए सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि आगामी तीन दिवसों में ऐसी समस्त शिकायतों को निराकरण कर बंद किया जाए। अगली समय सीमा की बैठक में समीक्षा करने पर अगर ऐसी शिकायतें लंबित पाई जाती है तो संबंधित विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सीएम हेल्पलाइन के द्वारा प्राप्त शिकायतों की भी विस्तार पूर्वक समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने 50 दिवसों से अधिक लंबित शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर निराकरात करें। उन्होंने राजस्व विभाग की लंबित शिकायतों के संबंध में समस्त तहसीलदारों को निर्देशित किया है कि समीक्षा के दौरान जानकारी प्रस्तुत करने में किसी भी प्रकार के बहाने न दिए

जाएं। बार-बार हिदायत देने के बाद भी जो अधिकारी कार्य नहीं करेंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। उन्होंने सीएम हेल्पलाइन में खराब प्रदर्शन के लिए पी एच ई, महिला एवं बाल विकास, संस्थागत वित्त, सामाजिक न्याय स्वास्थ श्रम शिक्षा सहकारिता आदि विभागों को निर्देशित किया है कि हेल्पलाइन पोर्टल पर अपने प्रदर्शन सुधार पर विशेष ध्यान दें। कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन में जिले की रैंकिंग पर असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि किसी भी विभाग के लचर प्रदर्शन का असर संपूर्ण जिले की रैंकिंग पर पड़ता है प्रयास करें अपने कार्य में उत्कृष्टता लाए एवं एक्टिव मोड पर कार्य करें। कलेक्टर ने राजस्व, सहकारिता, महिला एवं बाल विकास विभागों पर शिकायतो के निराकरण में देरी के लिए एवं खराब प्रदर्शन पर नाराजगी व्यक्त की। कलेक्टर सुश्री मीना ने 500 दिन से ऊपर की शिकायतो के त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। समग्र आईडी में आ रही टेक्निकल प्रॉब्लम के संबंध मैं उन्होंने सभी सीईओ एवं सीएमओ को निर्देश दिए हैं कि शिकायतो का निराकरण करे। शिकायतकर्ता से बात कर के समाधान निकले। उन्होंने जिला पंचायत सीईओ को उक्त समस्या की सतत मॉनिटरिंग करने के लिए भी निर्देशित किया। कलेक्टर ने गौशालाओं के संचालन की भी समीक्षा की। उन्होंने जिले में संचालित शासकीय एवं अशासकीय गौशालाओं की वर्तमान स्थिति के संबंध में जानकारी ली तथा आगामी समय में कितनी और गौशालाएं संचालित की जाना बाकी है इसके संबंध में भी वस्तुस्थिति स्पष्ट की। उन्होंने सभी सीएमओ एवं जनपद सीईओ से निराश्रित पशुओं के लिए किए जा रहे कार्यों के संबंध में जानकारी प्रस्तुत करने के लिए कहा। किए जा रहे कार्यों पर असंतोष व्यक्त करते हुए कलेक्टर ने नाराजगी व्यक्त की एवं संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि शासकीय एवं अशासकीय गौशालाओं के अतिरिक्त प्राइवेट संस्थानों एन जी ओ अथवा अन्य जगहों को चिन्हित कर वहां पर अस्थाई व्यवस्था करें जिससे कि गोवंश सड़कों पर न जाए। उन्होंने निर्देशित किया है कि ऐसे समस्त पशुपालकों जिनके पशु सड़को पर पर जाते है उन पर पेनल्टी भी लगाए। उन्होंने सभी सी ई ओ एवं सीएमओ को निर्देशित किया है कि इस दिशा में विशेष प्रयास किए जाएं तथा जिम्मेदारी के साथ सभी कार्य करें। इसके लिए सभी अनुविभागीय अधिकारी अपने अपने अनुविभाग के अंतर्गत सभी सीईओ एवं सीएमओ से चर्चा कर के समाधान निकालें। कलेक्टर ने जल गंगा संवर्धन अभियान एवं रूफ वॉटर हार्वेस्टिंग के संबंध में भी सीईओ एवं सीएमओ को निर्देशित किया है कि लक्ष्य तय करके कार्य करें। जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत चिन्हित जल संरचनाओं के पुनरुत्थान की कार्य प्रगति की भी समीक्षा की। कलेक्टर ने सभी विभागों को निर्देशित किया है कि वृक्षारोपण अभियान का ब्याज व्यापक प्रचार प्रसार करें निजी एवं स्कूली संस्थाओं को, बच्चों को, समाज सेवीयो एवं अन्य जनप्रतिनिधियों से भी वृक्षारोपण करवाए। उन्होंने समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया है कि अगली समय सीमा बैठक के दौरान जल गंगा संवर्धन अभियान,वृक्षारोपण एवं रूफ वाटर हार्वेस्टिंग के संबंध में फोटो एवं आंकड़ों के साथ कार्य प्रगति पर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट असवान राम चिरामन को उक्त कार्य की सतत रूप से मॉनिटरिंग करने के लिए निर्देशित किया। कलेक्टर ने उपार्जन के संबध में मिल रही शिकायतों के निराकरण के लिए एसडीएम को इस संबध में सतत सुपरविजन एवं मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए साथ ही रकबा सत्यापन का कार्य भी बारीकी से करने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने उर्वरक वितरण का कार्य भी सुनियोजित ढंग से करने के स्पष्ट निर्देश दिए। कलेक्टर ने शासन द्वारा जारी सुशासन के संबंध में निर्देशों का कड़ाई से पालन करवाने के लिए समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया साथ ही अपने अधीनस्थ कार्यालय में एवं कर्मचारियों को भी उक्त निर्देश का पालन करवाए जाना सुनिश्चित कअर्ने के निर्देश भी दिए। कलेक्टर ने कहा है कि सभी कार्यालय एक पंजी संधारित करें जिसमें आने वाले लोगों की जानकारी, उनकी समस्या एवं अन्य समस्याओं की जानकारी रखी जाए। बैठक में जिला पंचायत सी ई ओ एस एस रावत, डिप्टी कलेक्टर डॉ बबीता राठौर, सिटी मजिस्ट्रेट असवन राम चिरामन, एवं जिले के अधिकारी उपस्थित रहे।

पत्नी की बेवफाई से आहत पति ने पत्नी सहित दो बेटों की हत्या कर.... की खुदकुशी

24 घंटे के अंदर हत्याकांड का खुलासा

उमेश कुशवाहा। सिटी चीफ ।

सतना, पत्नी की बेवफाई से आहत होकर पति ने पत्नी समेत दो मासूम बेटों की हत्या कर खुद अपनी इहलीला समाप्त कर ली। पत्नी और बच्चों का शव किराए के कमरे में मिला जबकि पति का शव तिघरा रेल ट्रैक पर मिला। पुलिस अधीक्षक आशुतोष गुप्ता ने सीसीटीव्ही और फारेंसिक साक्ष्य संकलन के आधार पर पत्रकार वार्ता में मामले का खुलासा किया।

सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के नजीराबाद स्थित हरदौल बाबा मंदिर के पास एक महिला और उसके दो बेटों की हत्या कर दी गई। जबकि पति का शव रेलवे ट्रैक पर मिला। सूचना मिलने पर पुलिस उपमहानिरीक्षक रीवा रेंज साकेत पांडेय व एसपी आशुतोष गुप्ता,सीएसपी महेन्द्र सिंह चौहान, थाना प्रभारी सिटी कोतवाली एवं सिविल लाईन सहित पुलिस बल ने घटना स्थल पहुंचकर मौका मुआयना किया और जांच पड़ताल तेज की। बताया गया कि चौधरी परिवार एक दिन पहले ही किराए के मकान में रहने नजीराबाद आया था। राकेश चौधरी जो तिघरा गांव का रहने वाला था। उसने नजीराबाद में हरदौल बाबा मंदिर के पास राजेश उर्फ कैदी प्रजापति के मकान में कमरा एक दिन के लिए किराए पर लिया था। वो मंगलवार को पत्नी संगीता 28 वर्ष, दो बेटों निखिल 8 वर्ष और ऋतिक 6 वर्ष के साथ यहां रहने आया था। बुधवार की सुबह जब कमरे से कोई आवाज नहीं आई तो मकान मालकिन चंदा देखने पहुंची। यहां संगीता और दोनों बच्चों का शव पड़ा मिला।

पुलिस अधीक्षक ने जानकारी में बताया कि पुलिस थाना कोतवालीको रेल्वे प्रशासन की ओर से सूचना मिली कि, किसी अज्ञात व्यक्ति का शव कटी हालात मे मृत अवस्था मे घटनास्थल 1174/09 (रेल्वे पोल के पास) तिघरा रेल्वे लाईन मे पडा हुआ है जो सूचना पर थाना कोतवाली मे मर्ग क्रं. 55/24 धारा 194 बीएनएसएस के तहत पंजीबद्ध कर जांच प्रारंभ की गई । घटनास्थल से महत्वपूर्ण साक्ष्य संकलन फारेंसिक अधिकारी महेन्द्र पटेल द्वारा किया गया एवं घटनास्थल मे डाग स्काड व फिंगरप्रिंट द्वारा भी साक्ष्य संकलन किया गया । जांच मे यह ज्ञात हुआ कि,मृतक राकेश चौधरी का विवाह मृतिका संगीता वर्मा के साथ करीबन 10 वर्ष पूर्व हुआ था जो शादी के बाद से तिघरा मे रह रहे थे । शादी से उनके दो पुत्र निखिल उम्र 08 वर्ष व ऋषभ उम्र 06 वर्ष थे । मृतिका संगीता वर्मा शादी शुदा होने के बाबजूद कमलेश चौधरी से मोबाईल से बातचीत करने लगी थी उन दोनो की

घनिष्टता ज्यादा हो गई थी । दिनांक 15.02.24 को मृतिका संगीता वर्मा अपने पति को बिना बताये अपने प्रेमी कमलेश के साथ घर से चली गई थी । उसके उपरांत वापस आने पर अपने पति राकेश चौधरी के साथ आकर रहने लगी थी । मृतिका अपने दोनों बच्चों को साथ लेकर पुनः कमलेश के साथ कटनी चली गई थी और उसी के साथ रह रही थी वही पर रहने के दौरान मृतिका संगीता चौधरी ने अपने लडके निखिल चौधरी का एडमीशन रघुवंश उच्चतर माध्यमिक विद्यालय , झिंझरी कटनी मे करवाया था दिनांक 29.06.2024 को स्कूल के एडमीशन फार्म मे बालक निखिल चौधरी के पिता का नाम कमलेश चौधरी लिखवाया था । जिसके उपरांत दिनांक 05.07.2024 मृतिका संगीता वर्मा पुनः वापस अपने पति के पास आ गई थी और अपने पति राकेश चौधरी के साथ रहने लगी थी और मृतक राकेश चौधरी अपनी पत्नि मृतिका संगीता के साथ आकर किराये का मकान ढूंढ रहे थे । वह अपने पति राकेश चौधरी के साथ ही रहने लगी थी ।मृतिका फिर भी अपने प्रेमी कमलेश से लगातार मोबाईल मे बात होती रहती थी । जांच में मृतक राकेश चौधरी के जो कपड़े घटनास्थल मे बरामद हुये है उन पर जो खून के धब्बे मिले है वह किसी व्यक्ति को सामने से धारदार हथियार से मारने पर आते है । इसी प्रकार के पैटर्न के खून के धब्बे घटनास्थल के कमरे मे मिले है । फोरेंसिक एवं सीसीटीवी साक्ष्य से स्पष्ट है कि, मृतक राकेश चौधरी अपनी पत्नि संगीता चौधरी के इस तरह से दूसरे व्यक्ति से प्यार करने और लगातार उससे मोबाईल मे बात करने को लेकर मृतक राकेश चौधरी द्वारा ही धारदार हथियार से अपनी पत्नि संगीता चौधरी व दोनों बच्चों की हत्या कर दिया है और स्वंय भी आत्मग्लानि वश रेल्वे लाईन मे जाकर आत्महत्या कर लिया है।

कार्यवाही मे इनका रहा योगदान उक्त कार्यवाही और मामले के खुलासे में महेन्द्र सिहं चौहान सीएसपी सतना , निरी. शंखधर व्दिवेदी , निरी. योगेन्द्र सिंह परिहार एवं टीम उनि दिलीप मिश्रा , सउनि अनिल त्रिपाठी, सउनि राजेश तिवारी, प्रधान आरक्षक राहुल सिंह, प्रधान आरक्षक विकास सिंह,प्रधान आरक्षक अखंड सिंह, प्रधान आरक्षक आकाश द्विवेदी,निरी. विजय सिंह , उनि अजीत सिंह , सउनि दीपेश , प्रआर बीपेन्द्र मिश्रा , प्रआर. असलेन्द्र सिंह का योगदान रहा।

दुष्यंत सिंह पैड़ी ट्रांसप्लांटर से 15 एकड में कर रहे धान रोपाई

किसानों को धान की रोपाई के लिए पैडी ट्रांसप्लांटर मशीन एक बेहतर विकल्प है

मोहम्मद मुनीर। सिटी चीफ।

शहडोल, सशक्त और समृद्ध अन्नदाता भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है, इसलिए भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। कृषि रोजमर्रा की जिंदगी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और सभी जीवित चीजों के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। कम समय और हर समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए शहडोल जिले के जनपद पंचायत सोहागपुर के ग्राम पड़मानिया कला निवासी किसान दुष्यंत सिंह 15 एकड़ भूमि पर पैड़ी ट्रांसप्लांटर के माध्यम से धान की रोपाई कर रहें है।

दुष्यंत सिंह का कहना है कि पिछले 27 वर्षों से धान रोपाई का कार्य कर थे जिसमें श्रमिकों के साथ-साथ समय, पैसे की भी काफी दिक्कत होती थी। उक्त समस्याओं से निजात पाने के लिए कृषि अभियांत्रिकी विभाग से मै पैड़ी ट्रांसप्लांटर मशीन के लिए आवेदन किया। जिसमें मुझे डेढ़ लाख रूपये का अनुदान मिला और डेढ़ लाख रूपये स्वयं लगाकर पैड़ी ट्रांसप्लांटर मशीन प्राप्त किया। अब मै पैड़ी ट्रांसप्लांटर मशीन के माध्यम से 15 एकड़ में धान की रोपाई का कार्य रहा हूं अब मुझे श्रमिको के साथ-साथ पैसे और समय की भी बचत हो रही है। दुष्यंत सिंह ने कहा कि इस प्रकार कृषि उपकरणों में मिल रही छूट का लाभ हर किसान को लेना चाहिए जिससे किसान सशक्त हो सकें। उक्त कार्य के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एवं जिला प्रशासन को तहेदिल को धन्यवाद दिया।

इस बैंक लॉकर से गायब हो रही ग्राहकों की अमानत

बैंक कर्मी सहित एक अन्य पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज

मोहम्मद मुनीर। सिटी चीफ।

शहडोल, मामला सुनने में हैरान कर देने वाला है जिसमे एक बैंक पर ही धोखाधड़ी किये जाने का मामला सामने आया है, नगर के विवादों में हमेशा घेरे में रहने वाले यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बुढ़ार शाखा के लॉकर से उपभोक्ता एसईसीएल के रिटायर्ड कर्मचारी के खून पसीने की कमाई 20 लाख एफडी गायब होने का मामला सामने आया, लाकर में रखे जेवरात भी गायब होने की उपभोक्ता ने आशंका जाहरी करते हुए मामले की शिकायत थाने में की है, उपभोक्ता की शिकायत पर बुढार पुलिस ने एफडी की हेराफेरी करने वाले शातिर बदमाश सहित संलिप्त बैंक कर्मी के 409,420 के तहत मामला दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। बुढार यूनियन बैंक के लाकर में रखी जेवरात गायब होने व उपभोक्ता के पैसा की हेराफेरी का मामला अभी हाल में ही सोमवार को सामने आया था कि एक और इसी तरह का पहले भी मामला सामने आया है,जिससे बैंक साख पे कई तरह के सवाल खड़े कर दिया है। अनुविभाग क्षेत्र के अमलाई थाना क्षेत्र के रहने वाले कालरी के रिटायर्ड कर्मचारी कमलदास पनिका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बुढ़ार शाखा के उपभोक्ता है और उन्होंने अपनी

बेटी के नाम से एक लाकर भी लेकर रखा है, जिसमे उन्होंने जेवरात सहित महत्वपूर्ण दस्तावेज के साथ साथ 10-10 लाख की दो एफडी भी रखी थी, जिसका हर माह ब्याज उनकें खाते में आता था, लेकिन कुछ महीनो से मोबाइल पर मैसेज नही आने पीआर शंका हुई तो उपभोक्ता कमलदास बैंक में जाकर अपने खाते को चेक कराया तो उनके पैर के नीचे से मानो जमीन खिसक गई, उनके उनके 20 लाख की एफडी गायब थी, उपभोक्ता कमलदास का आरोप है की खुद को बैंक का कर्मचारी बताने वाला प्रकाश रावत बैक के अधिकारियों के साथ मिलकर उनके 20 लाख की एफडी का हेराफेरी किए है , इतना ही नहीं लाकर में रखे जेवरात भी गायब होने की उपभोक्ता ने आशंका जताते हुए मामले की शिकायत थाने में की है।

बैंक कर्मी सहित एक अन्य पर मामला दर्ज उपभोक्ता की शिकायत पर बुढार पुलिस ने एफडी की हेराफेरी करने वाले शातिर प्रकाश रावत सहित संलिप्त बैंक कर्मी के 409,420 के तहत मामला दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। इसके पूर्व भी लाकर से जेवरात गायब होने की शिकायत हुई थी। यूनियन बैंक में इसके पूर्व भी इसी तरह बैंक के लाकर से बुढार उपभोक्ता व्यापारी बल्लू विशनानी के लाकर से 20 लाख के जेवरात गायब होने की शिकायत हुई थी, तो वही बाबू लाल चौधरी नामक उपभोक्ता के खाते से पैसा गायब होने का मामला भी प्रकाश में आया था। बैंक प्रबंधक नहीं दे रहा स्पष्ट जवाब वही इस पूरे मामले बैंक प्रबंधन मिडिया के सामने कुछ भी कहने से मना कर रहें हैं।

इसी घटना की तर्ज पर हुई थी पिछली वारदात... मामले में इसी तरह जिले के बुढार थाना क्षेत्र के रहने वाले व्यवसायी के साथ घटना हुई दातूमल विशनदासानी का बुढार यूनियन बैंक में बचत खाता है। जिसमे उन्होंने जब से यूनियन बैंक में लाकर की सुविधा शुरू हुई तब अपने लाकर नम्बर 149 में अपने परिवार के जेवरात लेकर में रखे थे, इस दौरान वो आवश्यकता अनुसार लाकर खोलते बंद करते रहे, जिसके बाद किन्ही कारणों से उन्होंने लंबे समय से लाकर में रखे ज्वेलरी को न खोला और वो गायब निकली। उक्त घटना बीते 16 फरवरी 2024 की है और फिर यह घटना इसी बैंक में हो गयी। मामले में स्थानीय लोगो का कहना है की बिना बैंक मैनेजर की सहमति से बैंक में घपला हो जाना मुमकिन नहीं अब तो बैंक की विश्वसनीयता भी सवालों के घेरे में है।

प्रतिक्रिया...

यूनियन बैंक के एक उपभोक्ता के एफडी का पैसा गायब होने की शिकायत आई थी, जिस पर कार्यवाही करते हुए प्रकाश रावत सहित संलिप्त बैंक कर्मी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच पड़ताल की जा रही है।

संजय जायसवाल, थाना प्रभारी बुढ़ार

खेत में पानी की सिंचाई को लेकर विवाद

दो पक्षों में चले लाठी डंडे वीडियो

मोहम्मद मुनीर। सिटी चीफ।

शहडोल, जमीनी बात को लेकर दो पक्षों में मारपीट हुई है, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है इस घटना में आठ लोगों को चोट पहुंची है। घटना गोहपारू थाना क्षेत्र के मलमाथर की है। खेत में पानी की सिंचाई को लेकर विवाद हुआ था जिसमें मारपीट की घटना घटित हुई है। घटना का वीडियो गांव के एक शख्स ने बना लिया जो कि अब सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। इस खूनी जंग में खूब लाठी डंडे बरसाए गए ,महिलाओं को भी दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, इस हमले में किसी का सर फूटा तो किसी का हाथ टूटा, घायल यादव परिवार अपनी फरियाद लेकर एसपी कार्यालय पहुंचा जहा एसपी आफिस की फर्स पर लेट कर घायलों ने अपनी फरियाद सुनाते हुए गांव के दबंगों पर मारपीट का आरोप लगाया है, शहडोल पुलिस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। जमीनी विवाद में चले लाठी डंडे का लाइव विडियो सोसल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है।मलमाथर के रहने वाले यादव परिवार व शर्मा परिवार में खेत में पानी सीचने को लेकर विवाद हो गया , विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया को लाठी डंडे चलने लगे , दबंगों ने महिलाओं को भी दौड़ा दौड़ा कर लाठी डंडों से पीटा है। यादव परिवार की घायल महिला गोमती यादव ने आरोप लगाते हुए बताया कि खेत में पानी की सिंचाई को लेकर विवाद पर गांव के आशीष शर्मा, राजू शर्मा,दद्दू शर्मा,अंबिका शर्मा ने लाठी डंडे गैती आदि से हमला कर दिया, इस हमले मे यादव परिवार के 8 से अधिक लोगो चोटिल हुए है। डीएसपी राघवेंद्र दिवेदी का कहना है की गोहपारू के मलमाथर गांव में जमीनी मामले को लेकर शर्मा व यादव परिवार के बीच मारपीट हुई है ,जिस पर यादव परिवार के लोगो को चोट आई है शिकायत पर मामले की जांच के बाद कार्यवाही की जाएगी।

एसईसीएल श्रमिक आवास पर सटोरियों और नेताओ का कब्जा

अवैध गतिविधि संचालित, अफसरों की मौन स्वीकृति...?

मोहम्मद मुनीर। सिटी चीफ।

शहडोल। बुढार ग्रुप के अंतर्गत जो श्रमिक कॉलोनी आती है यहां पर सबसे अधिक अवैध कब्जों की भरमार देखी जा सकती है यहां बैठे जिम्मेदार लोग शिकायत मिलने के बाद भी इस पर किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं करते जिस कारण से ही अवैध कब्जे धारियों सकते हौसले बुलंद नजर आते हैं आज अगर कालोनियों का सर्वे करा लिया जाए तो बड़ी संख्या में अवैध कब्जा धारियों की संख्या देखी जा सकती है जो कि मुफ्त में बिजली और पानी का उपयोग कर रहे हैं। इसमें कई खद्दरधारी नेताओ के भी आशियाने तने है और तो और कुछ सटोरियों ने भी कालरी श्रमिको के लिए बने आवास पर कब्ज़ा कर लिया गया है और कुछ माननीयो ने श्रमिक आवास को तोड़कर दोमंजिला हवेली तान दी है, ऐसे में कोई बताये सबसे पहले किसके अवैध कब्जे को मुक्त करने की कार्यवाही की जानी चाहिये।

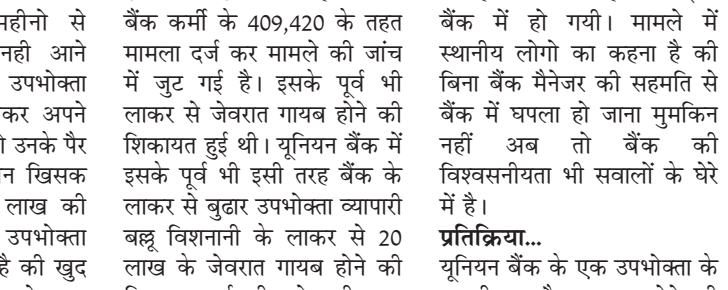

एसईसीएल सोहागपुर एरिया में व्यवस्थाओं को सुधारने की दिशा में प्रबंधन के कितना ध्यान होता है असल में यह कालोनियों में देख कर ही पता चलता है कभी सोहागपुर एरिया का मेन पावर 9000 के आस पास होता था साल बीतते गए और सेवानिवृत्त होते होते आज यह संख्या 4000 के आस पास पहुंच गई है लेकिन इसके बाद भी कर्मचारियों की सुविधाओं में प्रबंधन की ओर से कोई बढ़ोतरी की जा रही है यह भी दूर दूर तक देखने को नहीं मिल रहा है अब वर्तमान समय में देखा जाए तो लगभग आधा दर्जन से भी अधिक श्रमिक कॉलोनी है और इन कालोनियों में बड़ी मात्रा में अवैध कब्जे देखे जा सकते हैं इतना ही नहीं खाली आवासों का रखरखाव न होने के कारण अब यह खंडहर का रूप लेते जा रहे हैं दूसरी तरफ अवैध कब्जे को लेकर कई बार सर्वे किया जा चुका है लेकिन इसके बाद ही अवैध कब्जे को हटाने की दिशा में प्रबंधन की ओर से कोई कार्यवाही की जा रही हो यह भी दूर दूर तक देखने को नहीं मिल रहा है सवाल यह उठता है कि क्या अब प्रबंधन की जिम्मेदारी सिर्फ कोयला उत्पादन तक ही सीमित रह गई है कर्मचारियों की समस्याएं या फिर कालरी की संपत्तियों पर किए जा रहे कब्जों पर कार्यवाही को लेकर कोई ठोस प्रयास आखिर नजर क्यों नहीं आते।

पहले तो अवैध कब्जे धारियों के द्वारा 1 ही आवास पर कब्जा किया जाता था अब तो हालात ऐसे हो गए हैं कि एक व्यक्ति हैं 2 से लेकर 3 आवासों तक में कब्जा कर रखा है कैंप नंबर 1 कॉलोनियों में तो हालात इस तरह के हैं कि नए निर्माण तक करा दिए गए हैं और कार्यवाही को लेकर आज तक प्रबंधन की ओर से ध्यान नहीं दिया गया संजय नगर कॉलोनी में अगर देखा जाए तो यहां पर अवैध कब्जों की भरमार तो है लेकिन जो आवास खाली पड़े हैं रखरखाव न होने के कारण वह धीरे-धीरे खंडार का रूप लेते जा रहे हैं आखिर इन समस्याओं के समाधान को लेकर एरिया प्रबंधन कब ध्यान देगा यह अब एक सवाल बना हुआ है।

लक्ष्य : सप्ताह भर मे लगेंगे तीन सौ पौधे

पॉलीटेक्निक महाविद्यालय में वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम

मोहम्मद मुनीर । सिटी चीफ । शहडोल, शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय मे आज बुधवार को वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। जिसमे एक सौ पचास पेड़ लगाए गए। वहीं अगले एक सप्ताह में लगभग 300 पेड़ लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया है।वृक्षारोपण कार्यक्रम में छात्र छात्राओं एवम स्टॉफ सदस्यों द्वारा विद्यावन वाटिका विकसित करते हुए अनेक औषधीय, छायादार, फलदार पौधों के साथ साथ कुछ विशेष पौधे जैसे चंदन, बादाम एवम काजू के पौधे भी लगाए गए । उक्त कार्यक्रम जिला विधिक सेवा की सचिव एवम जिला न्यायाधीश कुमुदिनी पटेल के विशेष सहयोग, संस्था प्राचार्य जे आर रजक, संस्था ग्रीन कैंपस प्रभारी डॉ सादिक खान के मार्गदर्शन में सम्पन्न हुआ। उक्त कार्यक्रम में विभागाध्यक्ष सिविल इंजीनियरिंग रजनीश कुमार तिवारी, विभागाध्यक्ष मैकेनिकल इंजीनियरिंग श्रीमती प्रियंका शर्मा, विभागाध्यक्ष माइनिंग एवम माइन सर्वे इंजीनियरिंग पंकज तिलाटिया, संस्था के सभी व्याख्याताओं के साथ साथ अन्य अधिकारी कर्मचारी एम एल ध्रुव, दीपेंद्र मरावी, संदीप गुप्ता एवम स्टॉफ के सभी सदस्य, छात्र छात्राएं ,वरिष्ठ नागरिक एवम समाज सेवी ओपी महिन्द्रा ने विशेष योगदान दिया। उन्होंने छात्र छात्राओं का उत्साहवर्धन करते हुए लगभग 150 पेड़ लगवाए। संस्था ग्रीन कैंपस प्रभारी डॉ सादिक खान ने छात्र छात्राओं एवम संस्था परिवार के सभी सदस्यों से अहवाहन किया है पर्यावरण को संरक्षित करने हेतु अपने घरों एवम अन्य आसपास के सुलभ स्थानों में भी स्वयं और अपने रिश्तेदारों के द्वारा वृक्षारोपण कर संस्था प्राचार्य के व्हाट्सएप नंबर पर फोटोग्राफ भेजें और लगाए गए पौधों की देखरेख करते रहें।

मादा हथिनी पूनम ने दिया शावक को जन्म

स्वास्थ्य की देखभाल में जुटा प्रबंधन

मोहम्मद मुनीर । सिटी चीफ उमरिया, जिले के विश्वप्रसिद्ध बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में पूनम नामक मादा हथिनी ने शावक को जन्म दिया है। पार्क प्रबंधन के एक्सपर्ट वन्य जीव चिकित्सक एवं स्टाफ की मौजूदगी में पूनम ने सुरक्षित प्रसव किया है। पार्क प्रबंधन के उच्च अधिकारी हथिनी और शावक की देख देखा में जुटे हुए हैं।घटना पार्क के खितौली कोर परिक्षेत्र अंतर्गत अमिलिहा कैंप की है।

चार साल पूर्व निकाल ली राशि

नहीं बनी पीसीसी सड़क शिकायत के बाद भी नहीं हुई कार्यवाही

मोहम्मद मुनीर । सिटी चीफ । ब्योहारी, जनपद पंचायत ब्योहारी अंतर्गत ग्राम पंचायतो मे सरपंच एवं सचिवों द्वारा पंचायत को लूट का अड्डा बना कर रखा हुआ है। जब जी करता है तभी फर्जी बिल लगा कर राशि का आहरण कर लिया जाता है जिसे देखने सुनने वाला कोई नहीं है। जिम्मेदार अधिकारी भी चांदी के सिक्के की चमक के आगे चकाचौध हो कर रह गये है। लोग अपनी समस्या को कहे तो किस्से कहे उन्हें समझ मे नहीं आ रहा है। विडंबना इस बात की है कि कोई जानकार शिकायत भी करता है तो जिम्मेदार अधिकारी अपनी कोरमपूर्ति कर मामले को ठंडे बस्ते मे डाल देते है।

नहीं बनी सड़क, सरपंच सचिव ने डकार ली राशि ग्राम पंचायत पसगड़ी मे पदस्थ सचिव आशीष पाण्डेय एवं सरपंच बाबू लाल बसोंर ने वेंडर प्रशांत ट्रेडर्स से मिलीभगत कर फर्जी बिलो के आधार पर सीधी मुख्य मार्ग से सुखई साहू के घर तक 100 मीटर पीसीसी सड़क निर्माण के नाम पर वेंडर प्रशांत ट्रेडर्स के खाते मे चार साल पूर्व 215000 के लगभग राशि डाल कर बंदर बाट कर लिया गया है और आज तक पीसीसी सड़क का निर्माण नहीं कराया गया है।

वेंडर सहित सरपंच एवं सचिव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की उठ रही मांग मुख्य मार्ग से जुखई के घर तक पीसीसी सड़क निर्माण के नाम पर फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेज तैयार कर सरपंच बाबूलाल बसोंर एवं सचिव आशीष पाण्डेय द्वारा वेंडर प्रशांत ट्रेडर्स से मिली भगत कर शासकीय राशि का आहरण कर बंदर बाट कर लिया गया है जिसके लिये ग्रामीणों द्वारा सरपंच एवं सचिव सहित वेंडर के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज कराये जाने की मांग की जा रही है।

शिकायत के बाद भी नहीं हुई कार्यवाही ग्राम पंचायत मे पीसीसी सड़क निर्माण न करा कर राशि आहरण कर बंदर बाट किये जाने की जानकारी लगने पर गांव के निवासी अजय सिंह पेंड्रो द्वारा जनपद पंचायत ब्योहारी मे दिनांक 29/06/2024 को लिखित रूप मे शिकायत की गयी किन्तु जिम्मेदारो द्वारा उसे गंभीरता से नहीं लिया गया और कोई कार्यवाही नहीं होने की बात शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया जिस पर भी लोगों द्वारा सवालिया निसान लगाये जा रहे है।

इनका कहना है -

शिकायत प्राप्त हुई थी, जांच पर दोसी पाया गया है। प्रतिवेदन बना कर सीईओ साहब को दे दिया गया है।

उदयभान सिंह पेंड्रो - खंड पंचायत अधिकारी जनपद पंचायत ब्योहारी

कटनी में नाबालिक से दुष्कर्म के आरोपियों को अरेस्ट करने पहुंची पुलिस

ग्रामीणों ने आरोपियों को जूते चप्पल की माला पहना पूरे ग्राम में निकाला जुलूस

सुनील यादव । सिटी चीफ । कटनी, कटनी के माधवनगर थाना क्षेत्र निवार पुलिस चौकी अंतर्गत एक ग्राम में नाबालिक से दुष्कर्म के आरोपियों को अरेस्ट करने पहुंची पुलिस के सामने कई ग्रामीणों ने जूते चप्पल की माला पहना उनका पूरे ग्राम में जुलूस निकाला जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है।

कटनी जिले के संतोष डहरिया ने बताया की इस वीडियो में मामले में कटनी पुलिस जांच कर रही है दरअसल यह माधवनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत निवार पुलिस चौकी में आने वाले एक ग्राम में चौदह वर्षीय नाबालिग के साथ ज्यादती करने वाले आरोपी के विरुद्ध पुलिस ने अलग-अलग धाराओं के तहत मामला कायम कर लिया है। घटना से डरी-सहमी पीड़िता ने सोमवार को परिजनों के साथ एसपी अभिजीत रंजन के पास पहुंची थी। परिजनों और पीड़िता ने एसपी को आपबीती बताई। जिसके बाद एसपी ने त्वरित एक्शन लेते हुए माधवनगर थाने को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए जिसके बाद आरोपी के विरुद्ध कार्यवाही की गई। ओर आज आरोपी क़ो पकड़ लिया गया। आरोपी सुनील प्यासी ने नाबालिक को ट्रैक्टर में जबरन पहले अपहरण किया और नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया पीड़ित नाबालिक घटना के दिन अपने छोटे भाई के साथ तालाब के समीप घर के मवेशी को खोजने गई थी। उसी समय रास्ते में आरोपी ने ट्रैक्टर में पीड़िता को जबरन बैठा लिया। छोटे भाई ने विरोध जताया तो उसे ढकेल दिया। इसके बाद जंगल की तरफ लेकर गया और वहां पर दुष्कृत्य करने के बाद जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता ज्यादती की घटना से सहमी रही। उसकी बहन जब जबलपुर से आई तो उसने पूरी जानकारी दी। जिसके बाद 6 जुलाई को परिजन थाने पहुंचे हुए थे। यहां पर 6 जुलाई को महिला पुलिस अधिकारी ने बयान भी लिया था। आरोपी के विरुद्ध किसी तरह की कार्यवाही नहीं होने की जानकारी पीड़ित के परिवार ने सोमवार को एसपी को दी थी जिसके बाद आज माधव नगर पुलिस ने आरोपी क़ो गिरफ्तार कर लिया ब स्थानीय लोगों ने अचानक आरोपी सुनील प्यासी क़ो चप्पल की माला पहना कर गांव मे घुमाया द्य जिसकी वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रही है जिस वीडियो की पुलिस जांच कर रही है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दूध के लिए गए सैंपल

केमिकल और मिलावट युक्त दूध बेचने पर होगी कड़ी कार्रवाई

मोहम्मद मुनीर । सिटी चीफ । ब्यौहारी, नगर में काफी दिनों से मिलावटी दूध विकने खबरें आ रही थी समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों पर संग्यान लेते हुए खाद्य सुरक्षा अधिकारी एस के तिवारी द्वारा दिनांक 10/07/2024 को क ई दुध विक्रेताओं के सैंपल लेकर जांच हेतु भेजा गया जिन लोगों के सैंपल लिए गए उनमें कमलेश पाल ग्राम ताला मझौली, हीरालाल लाल यादव पिता रामप्रसाद यादव अनहरा पोस्ट जगमल ब्यौहारी- जिला शहडोल, शंकर यादव पिता चुनुआ यादव रतवार तहसील चुरहट जिला सीधी मप्र के सैंपल लेकर जांच हेतु भेजे गए हैं ईसके अलावा खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा संदीप ट्रेडर्स में भी जाकर खाद्य पदार्थों की जांच की एवं सभी ग्राहकों को खाद्य सामग्री के साथ बिल देने के निर्देश दिए खाद्य विभाग कि कार्रवाई से दूध विक्रेताओं में हड़कंप की स्थिति बन गई और कई लोग अपना दूध का डब्बा लेकर इधर-उधर गायब हो गए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एस के तिवारी ने दुग्ध विक्रेताओं मिलावट करने पर सख्त कार्रवाई की बात कही उन्होंने कहा कि कोई भी दुग्ध विक्रेता केमिकल ना मिलाये अपना लाइसेंस बनवा ले लाइसेंस एमपी ऑनलाइन के किसी भी दुकान से बन सकता है दुग्ध विक्रेता दूध बेचते समय अपना लाइसेंस और आधार कार्ड अपने साथ रखें बिना लाइसेंस दूध बेचते पाए जानें पर कड़ी करवाई की जाएगी

कब अवैध अतिक्रमण से मुक्त होगी सरकारी भूमि

मोहम्मद मुनीर । सिटी चीफ । शहडोल, जिले का जयसिंहनगर का बस स्टैंड में किया गया अतिक्रमण की शिकायत की फाइल नगरपालिका, तहसील और एसडीएम कोर्ट में धूल फाक़ रही है जबकि सूबे के मुख्यमंत्री ने विधानसभा चुनाव के बाद ही नई सरकार बनते ही अवैध कब्जाधारियों के विरुद्ध बड़ा एक्शन लेते हुए तल्ख़ लफ्जो में अवैध अतिक्रमण एवं सरकारी भूमि में किये गए कब्जे के लिए जवाबदार मन जायेगा, इस बयान के बाद पूरे मध्यप्रदेश में बेजा अतिक्रमण पर निरंतर कार्यवाही की जा रही है लेकिन शहडोल जिले का जयसिंहनगर का बस स्टैंड का अवैध अतिक्रमण बदस्तूर सरकारी मशीनरी को मुँह चिढ़ाता हुआ नजर आरहा है, यहाँ तानी इमारते बताती है की किस कदर राजस्व अफसरों की मिली भगत से करोडो रूपए की शासकीय भूमि तथाकथित लोगो द्वारा हड़प ली गयी है, सूत्रों के मुताबिक इस मांमले में हुई शिकायते सम्बंधित विभाग में डॉ तोड़ रही है, लेकिन जिम्मेदार अफसर अपनी सरकारी भूमि बचने में फ़ैल है।

एमएसडब्लू द्वारा वेतन को काट भुक्तान किए जाने से आक्रोशित हुए कर्मचारी

सफाई कर्मियों ने कांग्रेसियों के साथ कटनी नगर निगम का घेराव कर करा प्रदर्शन

सुनील यादव । सिटी चीफ । कटनी, कटनी नगर निगम का आज कांग्रेसियों के साथ डोर टू डोर कचरा उठाने वाले msw प्राइवेट के कंपनी के कचरा कलेक्ट करने वाले सफाई कर्मियों ने घेराव करते हुए जोरदार नारेबाजी कर प्रदर्शन किया ये सभी msw द्वारा कर्मचारियों के वेतन को काट भुक्तान किए जाने से नाराज थे वही आज एक दिवस के लिए सभी काम बंद हड़ताल पर है इनका कहना है की जब तक उन्हें कलेक्ट्रेट रेत पर वेतन नहीं मिलता वह काम पर वापस नहीं आयेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मिथलेश जैन ने बताया की ये सभी सफाई कर्मी msw प्राइवेट कंपनी के लिए काम करते है, msw प्राइवेट कंपनी नगर निगम सीमा क्षेत्र में डोर टू डोर कचरा उठवाने का काम करती है और इसका भुक्तान नगर निगम प्रशासन करती है। वही इस कंपनी में काम करने वाले सफाई कर्मी जो पहले कलेक्ट्रेट रेत पर इस कंपनी में काम करते थे इस माह उन्हे msw द्वारा उनका वेतन काट उनके खाते में डाली गई जिससे सभी कर्मी आक्रोशित है और एक दिवसी काम बंद हड़ताल पर है और आज कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ नगर निगम कार्यालय का घेराव किया और यह मांग की है की उन्हे कलेक्ट्रेट रेत पर वेतन दिया जाए वही नगर निगम कमिश्नर ने सभी कर्मचारियों को आश्वासन दिया है की वे msw के अधिकारियों से इस मामले में चर्चा कर समस्याओं का निराकरण कराएंगे।

देवबंद-रूडकी रेलमार्ग पर तीन माह में ट्रेनों का संचालन हो जाएगा शुरू

80 फीसद से ज्यादा पटरी बिछाने काम पूर्ण

गौरव सिंघल । सिटी चीफ । सहारनपुर, दिल्ली से हरिद्वार की दूरी काफी कम हो जाएगी और समय भी कम लगेगा। देवबंद से रूडकी के लिए रेल लाइन का निर्माण कार्य अंतिम स्थिति में है। देवबंद से रूडकी के बीच 27.54 किलोमीटर की रेल लाइन बिछाई जा रही है। 80 फीसद से ज्यादा पटरी बिछाने काम पूरा हो गया है। ध्यान रहे अभी रूडकी जाने के लिए टपरी से होकर जाना पड़ता है। जिसकी दूरी 60 किलोमीटर है और यदि सहारनपुर से होकर जाया जाए तो यह दूरी 76 किलोमीटर है। लेकिन देवबंद- रूडकी ट्रेक शुरू हो जाने के बाद यही दूरी घटकर 28 किलोमीटर से भी कम रह जाएगी। यह रेल लाइन सहारनपुर से 14 गांवों से और हरिद्वार जिले के 11 गांवों से होकर गुजर रही है। देवबंद-रूडकी रेलमार्ग की घोषणा वर्ष 2006 में की गई थी और इस काम को 2021 तक पूरा हो जाना था लेकिन कई कारणों से इसमें विलंब हुआ और अब ज्यादा से ज्यादा तीन माह में यह नया रेलमार्ग शुरू हो जाएगा। नए रेलमार्ग के शुरू हो जाने से सहारनपुर-दिल्ली और सहारनपुर-हरिद्वार मार्ग पर ट्रेनों का दबाव भी कम हो जाएगा और उनकी गति भी बढ़ेगी। दिल्ली- मेरठ-सहारनपुर रेलमार्ग बहुत ही व्यस्त है। नए रेलमार्ग पर बिजली के खंभे लगाने का काम भी तेजी के साथ हो रहा है। इसे जल्द से पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

वाशिंगटन शिखर सम्मेलनः NATO ने रूस चीन के बीच गहराते रिश्तों पर जताई चिंता

वाशिंगटन- उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) ने रूस और चीन के बीच गहराते संबंधों तथा बीजिंग की बढ़ती आक्रामकता पर बुधवार को चिंता जाहिर की। नाटो ने अपने वाशिंगटन शिखर सम्मेलन घोषणापत्र में कहा, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (पीआरसी) की महत्वाकांक्षाएं और आक्रामक नीतियां लगातार हमारे हितों, सुरक्षा और मूल्यों को चुनौती दे रही हैं। रूस और पीआरसी के बीच गहराती रणनीतिक साझेदारी तथा नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को कमजोर करने व नया आकार देने के दोनों देशों के प्रयास गंभीर चिंता का विषय हैं।

शिखर सम्मेलन में शामिल राष्ट्राध्यक्षों और शासन प्रमुखों की ओर से जारी घोषणापत्र में कहा गया है, हम सरकार में शामिल और उनसे इतर तत्वों से हाइब्रिड, साइबर, अंतरिक्ष और अन्य खतरों तथा दुर्भावनापूर्ण गतिविधियों का सामना कर रहे हैं। इस सम्मेलन में स्वीडन को नाटो के 32वें सदस्य देश के रूप में शामिल किया गया। घोषणापत्र में कहा गया है कि फिनलैंड और स्वीडन का नाटो में शामिल होना उन्हें सुरक्षित और संगठन को मजबूत बनाता है, 'हाई नॉर्थ% और बाल्टिक सागर क्षेत्रों में भी। इसमें कहा गया है कि यूक्रेन पर रूस के आक्रमण ने यूरो-अटलांटिक क्षेत्र में शांति और स्थिरता भंग कर दी है तथा वैश्विक सुरक्षा को गंभीर नुकसान पहुंचाया है।

घोषणापत्र में कहा गया है कि रूस संगठन के सदस्य देशों की सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण और प्रत्यक्ष खतरा बना हुआ है। इसमें कहा गया है, आतंकवाद, अपने सभी स्वरूपों और अभिव्यक्तियों में, हमारे नागरिकों की सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय शांति एवं समृद्धि के लिए सबसे प्रत्यक्ष खतरा है। हम जिन खतरों का सामना कर रहे हैं, वे वैश्विक और परस्पर जुड़े हुए हैं। सम्मेलन में नाटो ने अपनी प्रतिरोधक क्षमता और रक्षा तंत्र को मजबूत करने, रूस से लड़ाई में यूक्रेन को दीर्घकालिक समर्थन बढ़ाने और नाटो के सदस्य देशों के बीच साझेदारी को गहरा करने के लिए कदम उठाए। घोषणापत्र में कहा गया है, हम यूक्रेन के राष्ट्रपति (वोलोदिमीर) जेलेंस्की और ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड, कोरिया गणराज्य तथा यूरोपीय संघ के नेताओं का गर्मजोशी से स्वागत करते हैं।

भारत जल्द तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगाः ऑस्ट्रिया में बोले मोदी

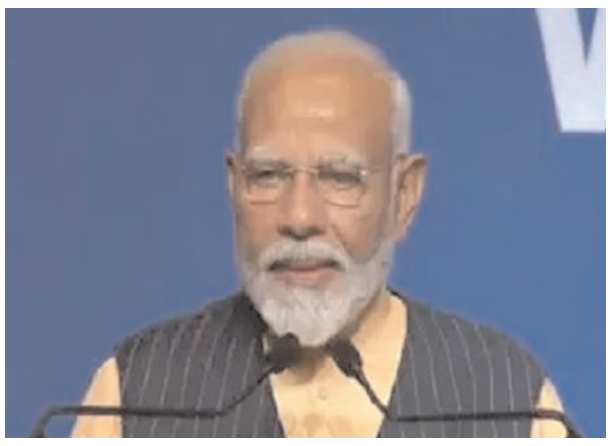

नेशनल डेस्कः प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को ऑस्ट्रिया की कंपनियों को भारत की 'शानदार विकास गाथा' में शामिल होने का न्योता दिया। उन्होंने कहा कि वे घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों के लिए 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम के तहत उच्च गुणवत्ता और लागत प्रभावी विनिर्माण का लाभ उठा सकती हैं।

ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेहमर के साथ उद्योग जगत के प्रमुखों को अपने संबोधन में मोदी ने सेमीकंडक्टर, चिकित्सा उपकरण और सौर पीवी सेल सहित अन्य क्षेत्रों में वैश्विक विनिर्माण कंपनियों को आकर्षित करने के लिए भारत की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना का विशेष रूप से उल्लेख किया।

विदेश मंत्रालय के बयान के अनुसार, प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रिया के उद्योगपतियों से भारत में तेजी से उभर रहे अवसरों पर गौर करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भारत अगले कुछ वर्षों में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रहा है।

प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार शाम रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के बाद दो दिवसीय यात्रा पर मंगलवार शाम मॉस्को से यहां पहुंचे। यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 साल से अधिक समय बाद ऑस्ट्रिया की पहली यात्रा है। मोदी ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर लिखा, ''भारत और ऑस्ट्रिया उद्योगपतियों से मुलाकात की। दोनों देश वाणिज्यिक और व्यापार संबंधों को बढ़ावा देने के लिए आने वाले कई अवसरों का लाभ उठाने के लिए आश्वस्त हैं।''

नाइजीरिया में हथियारों से लैस बंदूकधारियों ने 10 लोगों को उतारा मौत के घाट

अबुजाः नाइजीरिया के दक्षिण-मध्य राज्य बेन्यू में मंगलवार देर रात एक स्थानीय समुदाय पर संदिग्ध बंदूकधारियों के हमले में कम से कम 10 लोग मारे गए। एक स्थानीय सरकारी अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। बेन्यू के अगातु स्थानीय सरकारी क्षेत्र के प्रमुख फिलिप एबेन्याक्कू ने मीडिया को बताया कि बंदूकधारियों ने मंगलवार रात राज्य के अगातु स्थानीय सरकारी क्षेत्र के ओलेगुमाची समुदाय में कई घरों को ध्वस्त करके और कहर बरपाया।

एबेन्याक्कू ने कहा कि बंदूकधारी अत्याधुनिक हथियारों से लैस थे। उन्होंने स्थानीय लोगों के घरों को लूट लिया और खाद्य पदार्थों और पशुओं को लूट लिया, जबकि कम से कम सात अन्य घरों में आग लगा दी। उन्होंने बताया कि घटना की सूचना बुधवार तड़के स्थानीय पुलिस को दी गई।

कनाडा सरकार इन कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज के स्टडी परमिट पर लगा सकती है पाबंदी

ओटावा- कनाडा उन कॉलेजों, यूनिवर्सिटीज के लिए अध्ययन परमिट की प्रक्रिया बंद कर देगा जो अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को ट्रैक करने में विफल रहते हैं। इमिग्रेशन मंत्री मार्क मिलर अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की वृद्धि को रोकने के लिए बदलाव कर रहे हैं। प्रस्तावित नियम कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज को संघीय आव्रजन विभाग को यह रिपोर्ट करने के लिए बाध्य करेंगे कि कोई छात्र स्कूल जा रहा है या नहीं और अध्ययन परमिट की सभी आवश्यकताओं का अनुपालन कर रहा है या नहीं।

यह कदम कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय छात्र कार्यक्रम में विश्वास बहाल करने के हालिया प्रयासों का हिस्सा है। इमिग्रेशन अधिकारियों ने कहा कि संशोधन उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए उपकरण प्रदान करेंगे कि केवल वास्तविक कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज ही अध्ययन परमिट के लिए पात्र होंगे।

छात्र की स्वीकृति की पुष्टि करने के लिए आव्रजन विभाग के अनुरोध का जवाब देने के लिए 10 दिन दिए जाएंगे। उनके पास प्रत्येक छात्र की नामांकन स्थिति और वे सक्रिय रूप से अपना पाठ्यक्रम जारी रख रहे हैं या नहीं, इस बारे में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 60 दिन भी होंगे।

भारतीय मूल की ब्रिटिश सांसद शिवानी राजा ने हाथ में श्रीमद्भागवत गीता लेकर ली शपथ

इंटरनेशनल डेस्कः ब्रिटेन में भारतीय मूल की कंजर्वेटिव सांसद शिवानी राजा ने आज संसद में भगवदगीता पर सांसद के रूप में शपथ ग्रहण की। शिवानी लीसेस्टर ईस्ट सीट से जीतकर संसद पहुंची है। उन्होंने लेबर उम्मीदवार राजेश अग्रवाल को 14 हजार से अधिक वोटों से मात दी थी। बता दें यह सीट लेबर पार्टी का गढ़ मानी जाती थी। 1987 से यहां से लेबर उम्मीदवार ही जीत कर ससंद पहुंचा है। शिवानी ने एक्स पर लिथा कि लीसेस्टर ईस्ट का प्रतिनिधित्व करने के लिए आज ससंद में शपथ ग्रहण करना गर्व और सम्मान की बात है। भगवदगीता पर राजा चार्ल्स के प्रति अपनी निष्ठा की शपथ लेने पर गर्व है।

ब्रिटिश संसद में इस बार कुल 27 भारतीय मूल के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। इस बार 263 महिला उम्मीदवार जीतकर संसद पहुंची है, जो कुल सीट का 40 प्रतिशत है। इस बार सबसे अधिक 90 अश्वेत उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की। कीर स्टार्मर ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ब्रिटिश संसद में 650 सीटें हैं, जिनमें से लेबर पार्टी ने 412 सीटों पर दर्ज की। वहीं, कंजर्वेटिव पार्टी सिर्फ 121 सीटें ही जीत पाई। इस बार लेबर पार्टी का वोट शेयर 33.7 प्रतिशत था वहीं, कंजर्वेटिव पार्टी का वोट शेयर 23.7 प्रतिशत था।

बिजली गिरने से पूरे उत्तर प्रदेश में एक दिन में कम से कम 37 लोगों की मौत

नेशनल डेस्क- बिजली गिरने से पूरे उत्तर प्रदेश में एक दिन में कम से कम 37 लोगों की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश में बिजली गिरने से बुधवार (10 जुलाई) को उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के विभिन्न हिस्सों में बिजली गिरने से कम से कम 37 लोगों की मौत हो गई। प्रतापगढ़ में पुलिस और जिला प्रशासन की संयुक्त टीमें स्थिति की समीक्षा कर रही हैं और कहा कि मृतकों के परिजनों को कृषक दुर्घटना सहायता योजना के तहत मुआवजा प्रदान किया जाएगा।

ये मौतें प्रतापगढ़ जिले के संग्रामगढ़, जेठवारा, अंतू, मानिकपुर और कंधई पुलिस सर्कल में दर्ज की गईं। पुलिस ने कहा कि बुधवार शाम मानिकपुर पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में बिजली गिरने के अलग-अलग मामलों में अटौलिया, अगोस और नवाबगंज के रहने वाले 20 वर्षीय क्रांति विश्वकर्मा, 40 वर्षीय गुड्डु सरोज और 45 वर्षीय पंकज त्रिपाठी सहित तीन लोगों की मौत हो गई।

एक अन्य व्यक्ति, जिसकी पहचान 24 वर्षीय शिव पटेल और मन्नार निवासी के रूप में हुई है, को बिजली के संपर्क में आने के बाद इलाज के लिए रायबरेली के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कंधई पुलिस सर्कल के अंतर्गत, पुरषोत्तमपुर निवासी 45 वर्षीय अर्जुन और 40 वर्षीय उनकी पत्नी सुमन की बुधवार शाम पुरषोत्तमपुर गांव में उस समय बिजली गिरने से मौत हो गई, जब वे खेत में काम कर रहे थे।

कारपेंटर ने मजदूरी करके पत्नी को पढ़ाया...लेखपाल बनते ही पति को छोड़ा, अब दर-दर भटका रहा पति

नेशनल डेस्क- झांसी में धोखेबाज पत्नी का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। एक युवक जो अपनी पत्नी को पढ़ाने के लिए दर-दर भटकता रहा और जब पत्नी को पढ़ा लिखा कर लेखपाल बना दिया तब पत्नी ने उसका साथ छोड़ दिया। पत्नी के लिए वह पुलिस से लेकर अधिकारियों के चक्कर लगा चुका है लेकिन उसे न्याय नहीं मिला। इस बीच बुधवार को पत्नी को लेखपाल के पद के लिए नियुक्ति पत्र मिला वहां भी उसे खोजने के लिए गया लेकिन निराशा हाथ लगी।

पीड़ित शख्स झांसी की शहर कोतवाली अंतर्गत बाहर बाबा का अटा में रहने वाला नीरज विश्वकर्मा है। नीरज तीन भाई हैं, जिनमें वह सबसे छोटा है। नीरज विश्वकर्मा कारपेंटर का काम करता है और करीब 5 साल पहले झांसी के सत्यम कॉलोनी में रहने वाली रिचा सोनी से मुलाकात हुई थी जिसके बाद दोनों ने करीब ढाई साल बाद ओरछा मंदिर में जाकर शादी कर ली और हंसी-खुशी से रहने लगे।

इस दौरान लड़की रिचा ने उसे बताया था कि वह आगे पढना चाहती है, रिचा को पढ़ाने के लिए वह मजदूरी करता था। जब रिचा का सरकारी नौकरी लेखपाल में चयन हो गया तो फिर उसके तेवर बदल गए और उसे छोड़कर चली गई।

नीरज ने बताया, मैं 18 जनवरी से परेशान हूं, मेर धर्मपत्नी रिचा सोनी, जोकि अब लेखपाल बन गई हैं। इसलिए मुझे छोड़कर चली गई हैं। जिस कारण मैं दर-दर भटक रहा हूं। पति ने कहा कि हमने रिचा को पढ़ाने के लिए कारपेंटर का काम किया उसने जो चाहा उसने किया, हम 400 रुपए प्रतिदिन कमाते थे. उसी से उसकी पढ़ाई कराई, कई बार तो कर्ज भी लेना पड़ा, आज हम दिन रात उसे याद करते हैं, रात में नींद भी नहीं आती है। आज वह कहती है कि हमारी शादी नहीं हुई है। हमारे पास शादी की फोटो और प्रमाणपत्र है। वहीं दूसरी ओर लड़की का कहना है कि उसने नीरज के साथ शादी ही नहीं की।

संविधान बदलने के प्रचार से उत्तर प्रदेश में घटी एन.डी.ए. की सीटेंः अनुप्रिया पटेल

नेशनल डेस्क- उत्तर प्रदेश में हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों में हुई भाजपा की हार की समीक्षा को लेकर बवाल मचा हुआ है। भाजपा और इसके घटक दल के नेता चुनावों में खराब प्रदर्शन के लिए अलग-अलग तर्क दे रहे हैं। वहीं अब स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री और अपना दल (सोनेलाल) की प्रमुख अनुप्रिया पटेल ने मीडिया को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि उनकी पार्टी ने सात चरणों के चुनावों में से तीसरे चरण तक ही अनुमान लगा लिया था कि भारत के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य में सत्तारूढ़ गठबंधन के लिए सब कुछ ठीक नहीं है। यू.पी. में खराब प्रदर्शन को लेकर उन्होंने कहा कि विपक्ष आम जनता को समझाने में कामयाब रहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एन.डी.ए.) 400 से अधिक सीटें जीतने पर संविधान बदल देगा।

चुनावी नतीजों ने हैरत में डाला

अनुप्रिया पटेल कि देश के आम मतदाता का पी.एम. मोदी के नेतृत्व में विश्वास बरकरार है, यही वजह है कि हमें तीसरी बार लोगों की सेवा करने का मौका मिला है। वह कहती हैं कि इस सरकार से लोगों की जो भी अपेक्षाएं हैं, हम उन्हें पूरा करने में सक्षम होंगे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश ने हैरान कर दिया क्योंकि लोगों को उस परिणाम की उम्मीद नहीं थी। यह सही है कि यू.पी. में नतीजे हमारी उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहे। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि शुरू में सब कुछ ठीक था। लोग केंद्र सरकार के काम से खुश थे। जहां तक विकास की पहल का सवाल है, यू.पी. में बदलाव आया है, लेकिन जब आंकड़े आए तो यह चौंकाने वाले थे।

आरक्षण छीनने की अफवाह

पटेल कहती हैं कि हमें तीसरे चरण से छठे, सातवें चरण की ओर बढ़ने पर कुछ संकेत मिलने लगे थे। हमें एहसास हुआ कि संविधान का बदलने की अफवाह विपक्ष धीरे-धीरे फैलाने और मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा है। कहा जा रहा था कि संविधान द्वारा एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. को दिया जाने वाला आरक्षण मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में छीन लेगी। यह सब वायरल होता रहा और विपक्ष को मौका मिल गया क्योंकि उनके पास और कुछ नहीं था।

अफवाह फैलाने में कामयाब हुआ विपक्ष

अनुप्रिया पटेल ने कहा कि हमारे अपने ही कुछ लोगों ने कुछ इस तरह की बातें कहीं कि जब हमें 400 से ज्यादा सीटें मिल जाएंगी तो हम ये करेंगे या वो करेंगे। विपक्ष ने बहुत ही चतुराई से इसे कुछ ऐसा पकड़ लिया कि उन्हें लगा कि इसी पर काम करना चाहिए, क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ भी ठोस नहीं था। विपक्ष का मानना था कि अगर वे इस अफवाह पर काम करेंगे, तो वे शोषित वर्गों के मन में डर पैदा कर पाएंगे, और वे किसी तरह इसमें सफल भी हुए।

विकास को आगे बढ़ाना ही लक्ष्य

हालांकि समय के साथ लोगों को एहसास होगा कि विपक्ष ने उनके दिमाग और उनकी भावनाओं के साथ कैसे खेला है और उन्हें एहसास होगा कि कहीं न कहीं उन्होंने हमारी सरकार और हमारे गठबंधन द्वारा किए गए काम के साथ न्याय नहीं किया है, फिर भी हम नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश की विकास की कहानी को आगे बढ़ाते रहेंगे।

आरोपी और दोषी होने के बावजूद स्वयंभू भगवानों के आगे क्यों नतमस्तक हैं देश के लाखों लोग !

नेशनल डेस्क- हाथरस में स्वयंभू भगवान नारायण हरि साकर उर्फ भोले बाबा के सत्संग में मची भगदड़ में भले ही 121 लोगों की जान चली गई लेकिन देश में ऐसी घटनाओं से लोगों की बाबाओं के प्रति आस्था में जरा भी कमी नहीं आती है। हैरत की बात तो यह है कि कई बाबा ऐसे हैं जिन पर कई गंभीर आरोप हैं और जेल में बंद होने के बावजूद लाखों भारतीय आज भी नतमस्तक होते हैं। हाथरस की घटना ने भी देश के एक बड़े शहरी तबके को आश्चर्यचकित कर दिया होगा कि इतने सारे लोग बाबा के आश्रम में उनके पैरों की मिट्टी या उनके सत्संग में दिए जाने वाले पवित्र जल को हाथ लगाने के लिए क्यों आते हैं? विडंबना तो यह है कि नारायण हरि साकर उर्फ भोले बाबा की तरह, कई स्वयंभू बाबाओं ने एक बड़ी संख्या में अनुयायी जुटाए हैं। इन्ही के दम पर वे आलीशान स्विमिंग पूल और हरियाली वाले विशाल आश्रमों में लग्जरी लाइफ जीते हैं। वे दर्जनों स्वयंसेवकों के साथ एस.यू.वी. में घूमते हैं और अक्सर राजनेताओं, फिल्मी सितारों और अन्य मशहूर हस्तियों के संरक्षण का आनंद लेते हैं। नारायण हरि साकर के एक सेवक अवदेश माहेश्वरी के हवाले से एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि उनके अनुयायी देश भर से आते हैं, लेकिन वे मुख्य रूप से निम्न मध्यम वर्ग से हैं।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक श्रीमती ज्योती मिश्रा द्वारा कॉम्पेक प्रिंटर्स प्रा. लि. फ्री प्रेस हाउस 3/54, प्रेस कॉम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 45ए गुप्ता चैम्बर पहली मंजिल जावरा कंपाउंड इंदौर, (म.प्र.) से प्रकाशित।
प्रधान सम्पादक : अशीष मिश्रा आर.एन.आई. पंजीयन क्रमांक : एमपी/एच/आइएन 2009/34385 फोन नं : 0731-4202569 फैक्स नं : 0731-4202569